PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 324 ● भिलाई, गुरुवार 09 जुलाई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

संक्षिप्त समाचार

तृणमूल फंड मामले में बंगाल में कई ठिकानों पर छापे

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से जुड़े मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 150 करोड़ से ज्यादा के संदिग्ध लेनदेन की पहचान की है। शक है कि इन पैसों को कई कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इधर-उधर किया गया। ईडी यात्रा और एविएशन सर्विस से जुड़ी कई कंपनियों की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के सबूत मिले हैं। इस मामले में केयरवेल एविएशन नाम की एक कंपनी ईडी की जांच के दायरे में आ गई है। सूत्रों का कहना है कि यह कंपनी अभिषेक बनर्जी समेत तमाम हस्तियों को एयर चार्टर सर्विस देती थी। आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता में पांच जगहों पर तलाशी ली और कई दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ज़ब्त किए। जांच करने वाले अधिकारी अब इन ज़ब्त की गई चीज़ों की जांच कर रहे हैं ताकि गैर-कानूनी वित्तीय लेन-देन के शक की पुष्टि की जा सके।

दिल्ली की सड़कों पर उतरीं 300 नई इलेक्ट्रिक बसें

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सोमवार को बड़ी मजबूती मिली हैं. केंद्रीय गृह मंत्री ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन बसों के संचालन के साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 4,838 हो गई है, जबकि सार्वजनिक बसों का कुल बेड़ा अब 6,593 बसों तक पहुंच गया है. दिल्ली देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं. जिन बसों को आज हरी झंडी दी गई ये सभी बसें 9 मीटर लंबी हैं. इन्हें विशेष रूप से उन मार्गों पर चलाया जाएगा, जहां बड़ी बसों का संचालन कठिन होता है. इन बसों के शुरू होने से कॉलोनियों, मेट्रो स्टेशनों व प्रमुख बस टर्मिनलों के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी. जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी. इलेक्ट्रिक बसों के बढ़ते बेड़े से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी.

केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सिया ने प्रेमी चेतन से पहले ही कर ली थी शादी

पुणे। पुणे के चर्चित लोहागढ़ किला हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी सिया गोयल ने कारोबारी केतन अग्रवाल से तय शादी से कई महीने पहले ही अपने प्रेमी चेतन चौधरी से कथित तौर पर गुपचुप शादी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक, सिया गोयल और चेतन चौधरी ने करीब चार महीने पहले स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराया था। हालांकि, इसी साल फरवरी में सिया की सगाई पुणे के 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से हुई थी और दोनों की शादी नवंबर में होने वाली थी। बता दें कि 18 जून को लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की खाई में

चीन के गांसु में भयंकर भूस्खलन

अभी तक 21 लोगों की दर्दनाक मौत और 7 लोग घायल

नई दिल्ली/ एजेंसी

उत्तर-पश्चिमी चीन के गांसु प्रांत में मंगलवार सुबह एक बहुत ही भयंकर प्राकृतिक आपदा आई है। लोंगनान शहर के नान्हे टाउनशिप के रेनजांग गांव में अचानक हुए इस भारी भूस्खलन में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मलबे की चपेट में कुल 33 लोग आ गए थे, जिनमें से 7 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज जारी है। स्थानीय प्रशासन ने बुधवार को आधिकारिक रूप से बताया कि घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। राहत दल ने काफी कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि 21 की जान नहीं बची। सभी घायल लोगों का स्थानीय अस्पतालों में बेहतर इलाज चल रहा है और उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई गई है। घटना की खबर मिलते ही आपदा राहत, दमकल विभाग और पुलिस सहित कई अन्य बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए थे। इसके बाद पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य बहुत ही तेजी के साथ शुरू कर दिया गया था। चीन की सिन्हुआ समाचार एजेंसी के अनुसार, प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने स्थिति को देखकर लेवल-3 भू-आपदा रक्षा प्रतिक्रिया लागू कर दी है। इसके साथ ही एक बहुत ही स्पेशल वर्किंग ग्रुप भी राहत कार्य की निगरानी के लिए तुरंत मौके पर भेजा गया। इस बड़े बचाव अभियान में कुल 345 राहतकर्मियों और 10 खोजी कुत्तों को लोगों की तलाश में विशेष रूप से लगाया गया। मौके पर जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से भारी मलबा हटाया गया जबकि कई एंबुलेंस लगातार वहां तैनात रहीं। बचाव दलों ने लापता लोगों की तलाश, राहत और प्रभावित परिवारों के उचित पुनर्वास का काम भी बहुत तेजी से किया। गांसु प्रांतीय स्वास्थ्य आयोग ने इस आपदा से निपटने के लिए जिले में चार विशेष आपातकालीन मेडिकल टीमें तुरंत भेजीं। इन टीमों में आईसीयू, ट्रॉमा उपचार और बाल चिकित्सा यानी पीडियाट्रिक के बड़े और अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल थे। इसके अलावा 13 अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को भी इस बड़े और महत्वपूर्ण राहत कार्य में लोगों की मदद के लिए लगाया गया। गांसु प्रांतीय पीपुल्स हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर, ऑर्थोपेडिक्स और सामान्य सर्जरी के तीन विशेषज्ञों को भी सीधे मौके पर भेजा गया। प्रशासन ने घायलों के त्वरित इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और मरीजों के लिए दूरस्थ परामर्श की सुविधा भी शुरू की। विशेषज्ञों के अनुसार, चीन का लगभग 69 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है, जहां सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटें मौजूद हैं। कमजोर मिट्टी और भारी बारिश के कारण चीन भूस्खलन जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील देश है। इस दर्दनाक प्राकृतिक हादसे ने पूरे क्षेत्र के लोगों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है और वे दुखी हैं। हालांकि, चीनी प्रशासन और बचाव कर्मियों ने बहुत ही कम समय में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करके स्थिति को संभाला।

रेस्क्यू टीमों की कड़ी मेहनत के कारण कई लोगों की जान समय रहते बचाई जा सकी और घायलों को इलाज मिला। भविष्य में ऐसी आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचने के लिए अधिकारियों को अब और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

5 दिन से चल रहा था ऑपरेशन

लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर जाकिर गनी ढेर...

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जाकिर गनई को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी था और बुधवार को इसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों ने 3 जुलाई को शोपियां के मीमंदर क्षेत्र के एक घने बाग इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। यह इलाका दक्षिण कश्मीर के सात गांवों से घिरा हुआ है। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर सघन तलाशी शुरू की थी। अधिकारियों के मुताबिक, बुधवार को मुठभेड़ स्थल से फिर से गोलीबारी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की।

नाबालिग से लैंगिक उत्पीड़न मामला

कोर्ट ने फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने और उसके सहयोगी शाहरुख को सुनाई 5-5 साल की सजा....

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग बालिका से लैंगिक उत्पीड़न के मामले में तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने और उसके सहयोगी शाहरुख को दोषी ठहराते हुए दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही फूड इंस्पेक्टर द्वारा नाबालिग को अवैध रूप से नौकरी पर रखने और राशन कार्ड से जुड़े कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को निर्देश दिए हैं। अभियोजन के अनुसार, नाबालिग पीड़िता की माता ने थाना रामानुजगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि 11 जनवरी 2022 को तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने ने उनकी नाबालिग पुत्री को अपने कार्यालय में काम पर रखा था। आरोप था कि वह कार्यालय के कार्य के बहाने पीड़िता को अपने घर बुलाता था और उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी उसे नौकरी से निकालने और परिवार को जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि पीड़िता ने घटना की जानकारी आरोपी के ड्राइवर एस.आर.के. उर्फ शाहरुख को दी, लेकिन उसने भी आरोपी का साथ देते हुए पीड़िता को उसकी बात मानने के लिए कहा और नौकरी से निकलवाने की धमकी दी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में

चालान प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो), रामानुजगंज की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने तत्कालीन फूड इंस्पेक्टर निखिलेश टेम्भुर्ने को पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 तथा भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं में अधिकतम 5 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 24 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं सह-अभियुक्त शाहरुख को पॉक्सो अधिनियम की धारा 16/17 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों आरोपियों को जिला जेल भेज दिया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि नाबालिग को अवैध रूप से नौकरी पर रखने तथा राशन कार्ड से संबंधित कार्यों में कथित धन उगाही एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा कराई जाए।

डॉक्टर के साथ मारपीट मामले में बड़ा मोड़

शिंदे गुट के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे को पुलिस ने किया गिरफ्तार.....

नई दिल्ली/ एजेंसी

महाराष्ट्र के कल्याण में नगर निगम के अस्पताल के अंदर शिवसेना के कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और उनके तीन साथियों ने डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ से मारपीट की। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने रमेश म्हात्रे समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुहास हेमाडे ने कहा कि मारपीट के मामले में चार आरोपी हैं। इनमें स्थानीय कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे, अक्षय करंडे, राजेश पवार और प्रमोद निकम शामिल हैं। मारपीट की घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि एक महिला मरीज शास्त्री नगर अस्पताल आई थी। उसके इलाज को लेकर एक बात पर बहस हो गई। इसके बाद, मरीज के रिश्तेदार आरोपियों के साथ आए और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर वैभव सालुंखे, एक महिला डॉक्टर और एक नर्स के साथ मारपीट की। पुलिस अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, उन्हें पीटा, गालियां दीं और धमकाया। इस घटना के बाद, डॉ. वैभव सालुंखे ने शिकायत दर्ज कराई और मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने घटना की निंदा करते हुए कहा, चाहे डॉक्टर पुरुष हो या महिला, किसी के साथ मारपीट करना बहादुरी का काम नहीं है।

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' पर बढ़ा विवाद

नई दिल्ली। अभिनेता एवं गायक दिलजीत दोसांझ अभिनीत फिल्म 'सतलुज' प्रसारण मंच से हटाए जाने के बाद विवादों में घिर गई है। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म की विषय-वस्तु की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया है। समिति अपनी जांच पूरी करने के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। यह फिल्म पंजाब के मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और उनके लापता होने की घटना से प्रेरित बताई जा रही है। फिल्म की कहानी वर्ष 1990 के दशक में पंजाब में कथित गैर-कानूनी हत्याओं और जबरन अपहरण की घटनाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

विमान-हेलीकॉप्टर खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज

टीएमसी का 440 करोड़ रुपये वाले 3 बैंक खाते फ्रीज किया

नई दिल्ली/ एजेंसी

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालयने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए टीएमसी से जुड़े तीन बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपये जमा बताए जा रहे हैं। एजेंसी कथित संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और चार्टर्ड विमान व हेलीकॉप्टर खरीद से जुड़े मनी ट्रेल की जांच कर रही है। ईडी ने हाल ही में कोलकाता के करीब पांच स्थानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दायरे में केयरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज भी शामिल रही, जिसकी इकाई केयरवेल एविएशन प्राइवेट जेट किराए पर उपलब्ध कराती है। जांच का मकसद टीएमसी के खातों से जुड़े वित्तीय लेन-देन और विमान खरीद की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल करना है। ईडी की शुरुआती जांच के अनुसार, अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच टीएमसी के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किए गए। इसके बाद कंपनी ने 82.96 करोड़ रुपये एक नई कंपनी के खाते में भेजे। एजेंसी का दावा है कि इसी वित्तीय श्रृंखला के जरिए करीब 112 करोड़ रुपये का उपयोग 600 कॉरपोरेट विमान और हेलीकॉप्टर खरीदने में किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि हेलीकॉप्टर खरीद के लिए विदेश से प्राप्त धन का भी इस्तेमाल किया गया।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले

उद्योग,शिक्षा,पुलिस,कर व्यवस्था और नवा रायपुर को मिली नई दिशा

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, उद्योग, शिक्षा, कर व्यवस्था, पुलिस, पर्यावरण और बुनियादी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने कुल 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए निवेश बढ़ाने, व्यापार को सरल बनाने, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने, कर प्रणाली में सुधार तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों (सीपीएसयू) से खरीदी जाने वाली बिजली के भुगतान के लिए वर्तमान त्रिपक्षीय अनुबंध की जगह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप डायरेक्ट डेबिट मैंडेट व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। इससे एनटीपीसी सहित अन्य केंद्रीय विद्युत कंपनियों से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस विशेष कार्यपालिक बल (बस्तर फाइटर्स) की भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियम, 2026 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। यह निर्णय बस्तर क्षेत्र में विशेष बल को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन संबंधी संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति मिली। नए प्रावधानों के तहत विन्यास निधि के स्थान पर रक्षित निधि की व्यवस्था होगी तथा आधारभूत अधोसंरचना, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधाओं को यूजीसी और सक्षम नियामक संस्थाओं के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाएगा। इससे राज्य में गुणवत्तापूर्ण निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कर व्यवस्था को सरल बनाने की दिशा में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (वैट) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दी। जीएसटी लागू होने के बाद वैट संबंधी अपीलों में कमी आने के कारण वाणिज्यिक कर अधिकरण को समाप्त कर उसके लंबित मामलों को राजस्व मंडल को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे अपीलों का निपटारा अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संशोधन विधेयक, 2026 को भी स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य जीएसटी कानून को अधिक सरल बनाना, करदाताओं विशेषकर निर्यातकों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाले उद्योगों के लिए रिफंड प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाना है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई। अन्य अग्रणी राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन कर तैयार किए गए इस संशोधन से निवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनेगी तथा राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनिमय-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी। इस कानून के लागू होने पर छत्तीसगढ़ ऐसा विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। इसमें डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम आधारित निरीक्षण तथा दोहरे लाइसेंसिंग दायित्व समाप्त करने जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे उद्योगों और व्यापारियों के लिए प्रक्रियाएं अधिक सरल और समयबद्ध होंगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) द्वारा आवंटित भूखंडों एवं निर्मित परिसरों पर देय ब्याज और अधिभार में राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना-2026 को मंजूरी दी गई।

पट्टा सर्वे शुरू, अब घर-घर पहुंचेगा प्रशासन; 30 साल के नि:शुल्क पट्टे के लिए तेज हुई कवायद

कवर्धा। नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से आवासहीन परिवारों को भूमि का वैधानिक अधिकार दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद कवर्धा ने अभियान तेज कर दिया है। शासन की पट्टाधृति अधिकार नियम, 2023 के तहत पात्र परिवारों को 30 वर्षों के लिए शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित पट्टा सर्वे शिविर में पहले ही दिन 213 हितग्राहियों ने अपना पंजीयन कराया। प्रशासन का कहना है कि अब 9 जुलाई से डोर-टू-डोर सर्वे और दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन शुरू किया जाएगा, ताकि वास्तविक पात्र परिवारों तक योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सके। शिविर का आयोजन वीर सावरकर भवन एवं ठाकुर पारा स्थित सामुदायिक भवन में किया गया, जहां बड़ी संख्या में नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की तथा उन्हें निर्धारित प्रक्रिया की जानकारी भी दी। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केवल पात्र एवं आवासहीन परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा और प्रत्येक आवेदन का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार 9 जुलाई से गठित सर्वे दल नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में घर-घर पहुंचकर सर्वे करेगा। सर्वे के दौरान आवेदकों के निवास, दस्तावेज एवं पात्रता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार कर शासन को भेजी जाएगी, जिससे पट्टा वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अभियान को सफल बनाने के लिए 7 एवं 8 जुलाई को तीन स्थानों–वीर सावरकर भवन, पीजी कॉलेज डोम परिसर और ठाकुर पारा सामुदायिक भवन–में शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में आवेदन जमा करने के साथ-साथ नागरिकों को पट्टा सर्वे, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और नियमितीकरण की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सीएम हेल्पलाइन, पीएम आवास और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की कलेक्टर ने की समीक्षा

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, ऋषा ठाकुर सहित संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर उइके ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन, सीपीग्राम्स एवं पीएमओ पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को समय-सीमा में गंभीरतापूर्वक निराकरण करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण नहीं, बल्कि शिकायतकर्ता को नियमानुसार संतुष्टि भी होनी चाहिए। इसके अलावा उच्च कार्यालयों से प्राप्त सभी लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए सभी विभागों को वर्षा जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग अपने कार्यक्षेत्र के अनुरूप विभागवार कार्ययोजना (वर्किंग प्लान) तैयार कर जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ठोस पहल करे। बैठक में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनजागरूकता बढ़ाकर लोगों को अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि उन्हें सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिल सके। कलेक्टर उइके ने जिले में संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की तथा अधूरे कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग से खाद एवं उर्वरकों के सुचारु वितरण की जानकारी लेते हुए किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में सेवा सेतु पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वर्ष 2016 से 2023 तक स्वीकृत लेकिन अपूर्ण आवासों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने शेष सभी आवासों को जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल गोदग्राम योजना के अंतर्गत विद्युत एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही रोजगार सहायक, तकनीकी सहायक एवं संबंधित अमले को क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर उइके ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना सभी विभागों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से समन्वय और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शत् प्रतिशत आधार वेरिफिकेशन, स्कूली विद्यार्थियों का अपार आईडी, पीएम जनमन योजना के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति, विशेष पिछड़ी जनजातियों का आयुष्मान कार्ड, एग्रीस्टेक पंजीयन सहित अन्य कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए।

बेमेतरा के अंडर 18 रग्बी खिलाड़ियों ने जीता इस साल का तीसरा खिताब

बेमेतरा। राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता का खिताब बेमेतरा ने जीता रग्बी प्रतियोगिता जो की कोरबा के प्रिय दर्शनीय स्टेडियम टी पी नगर मे आयोजित थी, जिसमे बेमेतरा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी आत्मानंद स्कूल हसदा के अंडर 18 बालिकाओ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल मे महासमुंद की टीम को 15/5 से हराकर रग्बी प्रतियोगिता का खिताब जीता टीम ने अपने लीग मैच मे जहाँ बेमेतरा ने रायपुर को 30/0 और दुर्ग को 35/0 से वही बालोद को 10/0 और फिर सेमीफाइनल में बिलासपुर की टीम को 20/0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर महासमुंद की टीम को एकतरफा मैच में 15/5 से हराकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। बालिका टीम में द्रौपति निर्मलकर (कप्तान), गोमती, श्रद्धा, रोशनी, नंदनी, मानसी, भूमिका, सरस्वती , लावण्या, डिंपल, याचना, कुसुम व कोच दुलेश्वरी धीवर, रमजान अली, मैनेजर होमेंश्वरी निर्मलकर रही। यह जानकारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हसदा के व्यायाम शिक्षक लोकेश्वर राव ने दी। स्वामी आत्मानंद स्कूल हसदा बेमेतरा संस्था के प्राचार्य जी पी सिंह दुष्यन्त कुमार परगनिहा सरपंच चंद्रशेखर परगनिहा बलि राम धीवर संध्या परगनिहा, उपसरपंच ओमप्रकाश सिन्हा, जनपद सदस्य रेखा पौषण सिंह्रा, संकुल समन्वयक दीपक आड़ील, रामेश्वरी साहू व्यायाम शिक्षक, आकाश वर्मा, मानचंद निर्मलकर, देविका वर्मा, आंचल बंछोर ने खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की। साथ ही संस्था प्रमुख का कहना है कि ये खिलाडियों के कठिन परिश्रम का फल है। आपको बता दे कि यहाँ रग्बी की नई पौध तैयार की जा रही है। साथ ही उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। खिलाडियों को तैयार करने मे प्रमुख योगदान यहाँ के व्यायाम शिक्षक लोकेश्वर राव तथा रामेश्वरी साहू और आकाश वर्मा के द्वारा उनको और भी कई सारे खेल का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाता है। यह स्वामी आत्मानंद स्कूल हसदा के खिलाडियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ खिलाडियों ने साबित कर दिया की गाँव मे रहकर भी नई उचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है। बस मेहनत करनी पड़ती है, उनको तरासने के लिए ताकि वो एक अच्छा खिलाडी बन सके। ये कहना है यहाँ के व्यायाम शिक्षक लोकेश्वर राव जो खुद एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाडी है। यहाँ के खिलाड़ियों का इस वर्ष का यह तीसरा खिताब है।

सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता के लिए सिकल मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया

दल्लीराजहरा। सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता और मरीजों को सही मार्गदर्शन देने के लिए सिकल मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम शहीद अस्पताल दल्लीराजहरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिखलाकसा, जिला अस्पताल दुर्ग और जिला अस्पताल बालोद के संयुक्त तत्वावधान में शहीद अस्पताल परिसर में हुआ। शिविर में क्षेत्र के 107 सिकल सेल योद्धाओं और वाहकों का पंजीयन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहीद अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैबल जाना रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिखलाकसा की चिकित्सा अधिकारी डॉ. निधि और डॉ. मेरिया उपस्थित थीं। विशेषज्ञों ने उपस्थित मरीजों और उनके परिजनों को बीमारी के कारण, इलाज और आनुवांशिक परामर्श के महत्व की जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि यह आनुवांशिक बीमारी है। इसे अगली पीढ़ी में जाने से रोकने के लिए विवाह पूर्व युवक-युवतियों की रक्त जांच कराना जरूरी है। सम्मेलन में फिजियोथेरेपी के महत्व पर भी सत्र रखा गया। विशेषज्ञों ने बताया कि सही व्यायाम से मरीजों की शारीरिक क्षमता बढ़ती है।

नशा मुक्ति अभियान से अब तक 903 लोग हुए जागरूक

गरियाबंद। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अशोक कुमार पाण्डेय के निर्देश एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी अनिल द्विवेदी के मार्गदर्शन में जिला बाल संरक्षण इकाई, मिशन शक्ति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 द्वारा 17 जून से 01 जुलाई 2026 तक जिलेभर में नशा मुक्ति जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालयों, ग्राम पंचायतों, बस स्टैंड, होटल एवं ढाबों में युवाओं तथा आम नागरिकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। उन्हें नशे से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान, पारिवारिक कलह, अपराध, दुर्घटनाएं, आर्थिक, शारीरिक हानि तथा असमय मृत्यु जैसे गंभीर परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के माध्यम से जिले में 903 लोग लाभान्वित हुए। इस दौरान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, पॉक्सो अधिनियम, 2012, बच्चों के अधिकार, गुड टच-बैड टच, बाल विवाह निषेध एवं बाल श्रम कानूनों की भी जानकारी दी गई। आमजनों को 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह कानूनन अपराध की जानकारी साझा की गई।

श्रमिकों की ई-केवाईसी के लिए सीएससी संचालकों को दिया गया प्रशिक्षण

गरियाबंद। जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी एवं आधार अनुरूप डाटा संशोधन कार्य को गति देने के लिए अधिकृत 135 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिले के 37 हजार 697 पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु सीएससी संचालकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए प्रति ई-केवाईसी 20 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रमिकों के आधार अनुरूप डाटा संशोधन, ई-केवाईसी सत्यापन तथा ऑनलाइन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की विस्तृत जानकारी दी गई। श्रम विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से विशेष अभियान संचालित कर अधिक से अधिक पंजीकृत श्रमिकों की ई-केवाईसी एवं आवश्यक डाटा संशोधन का कार्य 31 जुलाई 2026 तक पूर्ण कराया जाएगा, ताकि पात्र श्रमिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। इस दौरान सहायक मैनेजर (बैंकिंग) रितेश शुक्ला ने प्रोजेक्टर के माध्यम से ऑनलाइन डाटा संशोधन प्रक्रिया का लाइव डेमो प्रस्तुत किया। उन्होंने श्रमिक कार्ड में नाम, पता, आधार संख्या सहित अन्य आवश्यक जानकारियों में संशोधन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया तथा त्रुटिरहित डाटा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सही और अद्यतन जानकारी होने से श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। प्रशिक्षण में श्रम पदाधिकारी जयंती बंसल, श्रम निरीक्षक परीक्षित कुमार, सहायक मैनेजर (बैंकिंग) रितेश शुक्ला तथा जिला सीएससी मैनेजर परमानंद साहू सहित जिले के सभी अधिकृत सीएससी संचालक उपस्थित रहे।

बरसात मे नाला सफाई पर महापौर सख्त, सोरिद वार्ड डिपोपारा में सफाई कार्य का किया निरीक्षण

धमतरी। शहर में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से नागरिकों को राहत दिलाने के उद्देश्य से महापौर रामू रोहरा ने पार्षदगण के साथ सोरिद वार्ड डिपोपारा में चल रहे नाला सफाई कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। महापौर रोहरा ने कहा कि बरसात के मौसम में जल निकासी व्यवस्था सुचारु बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नालों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण सफाई सुनिश्चित करने, कचरे का तत्काल उठाव करने तथा जल प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां.जहां आवश्यकता हो, वहां अतिरिक्त संसाधन लगाकर सफाई कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान वार्डवासियों ने भी वार्ड की विभिन्न समस्याओं से महापौर को अवगत कराया जिस पर महापौर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा और सुरक्षित बरसात को ध्यान में रखते हुए नगर निगम लगातार सभी वार्डों में नाला सफाई, जल निकासी एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों की निगरानी कर रहा है। महापौर ने नागरिकों से भी अपील की कि वे नालों में कचरा, प्लास्टिक एवं अन्य अपशिष्ट सामग्री न डालें तथा शहर को स्वच्छ एवं जलभराव मुक्त बनाने में नगर निगम का सहयोग करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी वार्डों में नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जाएगा।

एनडीपीएस एक्ट प्रकरण: दो तस्करों को सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

धमतरी। धमतरी जिले में एसपी के नेतृत्व में अवैध गांजा, मादक पदार्थ, अवैध शराब एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रत्येक प्रकरण की नियमित समीक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा मजबूत साक्ष्य संकलन के परिणामस्वरूप अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने में लगातार सफलता मिल रही है। 09 जनवरी 2024 को थाना बोराई पुलिस द्वारा थाना के सामने बैरियर नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही मारुति जेन एलएक्स कार क्रमांक एमपी 20 एफए 2513 को संदेह के आधार पर रोककर तलाशी ली गई। वाहन की डिक्की एवं बीच की सीट में रखी तीन प्लास्टिक बोरियों से 53 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। वाहन में सवार तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा निवासी जिला सतना मध्यप्रदेश तथा विजय विश्वकर्मा निवासी जिला रीवा मध्यप्रदेश गांजा के परिवहन एवं वाहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 किलोग्राम गांजा, मारुति कार, दो मोबाइल फोन एवं नकद राशि सहित कुल 11,10,800 रू. मूल्य की संपत्ति विधिवत जप्त की तथा दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 01/2024, धारा 20-बी दो सी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में धमतरी पुलिस द्वारा की गई निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं सुदृढ़ विवेचना तथा न्यायालय में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख अर्थदंड से दंडित किया है। यह निर्णय मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि धमतरी पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सशक्त अनुसंधान के सामने ऐसे अपराधियों को कानून के शिकंजे से बचना संभव नहीं है। आरोपियों में तोषण विश्वकर्मा उर्फ राजा पिता शारदा प्रसाद विश्वकर्मा उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक.15 गाजन थाना रामपुर बघेलान जिला सतना मध्यप्रदेश। विजय विश्वकर्मा पिता रामजी विश्वकर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी रतहरी थाना सिविल लाइन जिला रीवा मध्यप्रदेश। उक्त प्रकरण की तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि रामकृष्ण साहू द्वारा अत्यंत सूक्ष्मता, दक्षता एवं पेशेवर तरीके से की गई। उनके द्वारा संकलित मजबूत साक्ष्यों एवं गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के आधार पर न्यायालय से आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। एसपी धमतरी ने उत्कृष्ट विवेचना एवं प्रभावी साक्ष्य संकलन के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी सउनि. रामकृष्ण साहू को 500 रूपये की नगद पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं वैज्ञानिक विवेचना ही अपराधियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

नगर पालिका कुरूद में सभी मनोनीत एल्डरमेन का शपथ ग्रहण संपन्न

कुरूद। नगर पालिका कुरूद में सभी मनोनीत पार्षदों (एल्डरमेन) का शपथ ग्रहण कार्यक्रम एवं नये बिजली वाहन का अनावरण मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति भानु चन्द्राकर के गरिमामयी आतिथ्य में संपन्न हुआ। गरिमामयी सादे समारोह में कुरूद के एसडीएम ने नभसिंह कोसले ने सभी पार्षदों को बारी बारी करके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई, सबसे पहले नगरपालिका कुरूद मे तीन बार के पार्षद दो बार शासन की ओर से और एक बार निर्वाचित होकर अनुभवी एवं वरिष्ठ पार्षद भानु चन्द्राकर ने शपथ लिये पश्चात खिलावन यादव, चन्द्रकुमार (नंदू) चन्द्राकर, खिलेन्द्र देवांगन, महावीर साहू ने शपथ लिये। सभी मनोनीत पार्षदों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पीआईसी मेम्बरो, पार्षदों, पार्षदों, भाजपा मंडल अध्यक्ष, प्रेस क्लब अध्यक्ष एवं गणमान्य नागरिकों ने बुके-फूल माला से स्वागत वंदन कर बधाई दिये, शासन की ओर से शपथ दिलाने के बाद एसडीएम कोसले एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने भी सभी मनोनीत पार्षदों को बधाई दिये। शपथग्रहण के पश्चात उपमुख्यमंत्री अरूण साव एवं विधायक अजय चन्द्राकर के स्वीकृति से नगर में बहुत सारे संख्या मे बिजली पोल लग रहे जिसके मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए बड़ी बिजली वाहन शासन ने कुरूद नगरपालिका को सौंपे हैं जिसका विधिवत पुजा अर्चना कर नगरपालिका ज्योति भानु चन्द्राकर ने अनावरण कर नगरवासियों को समर्पित किये, नगरवासियों की ओर से बिजली वाहन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधायक का नगरवासियों की ओर से अध्यक्ष महोदया ने धन्यवाद ज्ञापित किये। इस पुण्य अवसर पर मुख्य आतिथ्य के रूप में ज्योति भानु चन्द्राकर अध्यक्ष नगरपालिका कुरूद, आतिथ्य के रूप में उपाध्यक्ष देवव्रत साहू, नेता प्रतिपक्ष डूमेश साहु, नभ सिंह कोसले सम्मिलित हुए। इस पुण्य अवसर पर साक्षी बनने भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णकांत साहु, पार्षदगण रजत चन्द्राकर, मनीष साहु, मिथलेश बैस, महेन्द्र गायकवाड़, रवि मानिकपुरी, कविता चन्द्राकर, राजकुमारी ध्रुव, गणमान्य नागरिकों मे प्रेस कलब अध्यक्ष मूलचंद सिन्हा, पत्रकार श्रवण साहु, खेमलाल देवांगन, भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष धनेश्वरी निर्मलकर, संजु चन्द्राकर, रोमन देवांगन, सुसील देवांगन, अजय देवांगन, देवकांत दिवेदी, हर्षित अग्रवाल, बल्लू चन्द्राकर, कमलेश चन्द्राकर, प्रवीण रेड्डी, राजू चन्द्राकर गणमान्य नागरिकगण एवं नगरपालिका कर्मी बहुत ही सादगी समारोह मे सम्मिलित हुए, सभी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ गुप्ता ने किया।

महापौर रामू रोहरा ने बरसात मे जलभराव की समस्या रोकने अधिकारियों की ली बैठक

धमतरी। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए महापौर रामू रोहरा ने नगर पालिक निगम के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर शहर सहित सभी वार्डों में जल निकासी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में नालियों की नियमित सफाई, जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान, बंद नालों को तत्काल साफ कराने तथा वर्षा के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। महापौर रामू रोहरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के किसी भी वार्ड में बारिश का पानी जमा नहीं होना चाहिए। जलभराव की संभावना वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए समय रहते आवश्यक कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि नालियों की सफाई, कचरे का नियमित उठाव तथा जल निकासी तंत्र को पूरी तरह सुचारु रखना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा फील्ड अमला लगातार निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर बनाए रखे। महापौर ने कहा कि बरसात के दौरान लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न होए इसके लिए निगम का पूरा अमला पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि नालियों में कचरा या प्लास्टिक न डालें तथा शहर को स्वच्छ बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें, ताकि बरसात के दौरान जल निकासी व्यवस्था सुचारु बनी रहे और जलभराव जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

संक्षिप्त समाचार

दोपहिया वाहन चोर गिरफ्तार, 5 चोरी की बाइक बरामद; 2 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

रायपुर। के उरला थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी के मामले में एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाइकिल बरामद की हैं। जब्त वाहनों की कुल कीमत करीब 2 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, प्रार्थी देवेंद्र साहू ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 जुलाई 2026 को वह उरला स्थित एक पेट्रोल पंप पर काम करने गया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप परिसर में खड़ी की थी, लेकिन काम खत्म कर लौटने पर वाहन गायब मिला। शिकायत के आधार पर थाना उरला में अपराध क्रमांक 305/2026 दर्ज कर धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा तथा थाना उरला पुलिस की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और मुखबिर तंत्र सक्रिय किया।जांच के दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अभय दुबे (30 वर्ष) बताया और बरामद मोटरसाइकिल के चोरी का होना स्वीकार किया।कड़ाई से पछताछ करने पर आरोपी ने शहर के अलग-अलग स्थानों से चार अन्य दोपहिया वाहन चोरी करने की बात भी कबूल कर ली।

नगर निगम के खिलाफ ठेकेदारों का हल्लाबोल, भुगतान और कमीशनखोरी के आरोपों पर काम बंद कर प्रदर्शन

रायपुर। रायपुर नगर निगम में बकाया भुगतान और कथित कमीशनखोरी को लेकर ठेकेदारों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर नजर आया। सिविल ठेकेदार संघ के बैनर तले ठेकेदारों ने नगर निगम मुख्यालय के सामने काम बंद कर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि बिना कमीशन दिए भुगतान की फाइलें आगे नहीं बढ़ाई जा रही हैं। ठेकेदारों का दावा है कि निगम पर 100 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है। कई ठेकेदारों को छह महीने से लेकर डेढ़ साल तक भुगतान नहीं मिला है। उनका कहना है कि बैंक से कर्ज लेकर काम करने वाले ठेकेदार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जबकि निगम में भुगतान के लिए कथित तौर पर अलग-अलग स्तर पर कमीशन की मांग की जाती है। प्रदर्शन के दौरान ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि हर फाइल का अलग रेट तय है और 30 से 40 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जाता है। उनका यह भी आरोप है कि अधिकारियों, जोन अध्यक्षों और जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी भुगतान के लिए हिस्सेदारी तय रहती है। साथ ही, अधिकारियों पर मुफ्त में अतिरिक्त काम कराने और बाद में देरी का ठीकरा ठेकेदारों पर फोड़ने का आरोप लगाया गया। सिविल ठेकेदार संघ के अध्यक्ष दुर्गेश ने कहा कि वर्तमान नगर निगम आयुक्त के कार्यकाल में व्यवस्थाएं और बिगड़ गई हैं।

नकटी मामले पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, मुख्यमंत्री निवास घेराव तक की तैयारी

रायपुर। नकटी गांव के प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस की जांच समिति की बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोकभवन में प्रदर्शन, राज्यपाल से मुलाकात और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी भी कर रही है।प्रदेश कांग्रेस जांच दल के सदस्य भावेश बघेल ने कहा कि सम्मानपुर-नकटी की घटना केवल गरीब परिवारों के घर उजाड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटना है। उन्होंने आरोप लगाया कि बुलडोजर कार्रवाई के बाद मलबे में बेजुबान पशुओं और गौ माता के दबे होने की जानकारी सामने आई, जो प्रशासन की संवेदनहीनता को दर्शाती है।

पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक, लोगों से 28 हजार मांग रहे साइबर ठग

रायपुर । जिले में साइबर ठग अब भाजपा नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर साइबर अपराधियों ने उनके परिचितों से यूपीआई के माध्यम से 28 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी है। तीन दिनों के भीतर किसी बड़े भाजपा नेता का व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने का यह दूसरा मामला है।जानकारी के अनुसार, हैकर गोवर्धन मांझी के नाम से उनके संपर्क में मौजूद लोगों को संदेश भेज रहा है कि नेटवर्क की समस्या के कारण तत्काल 28 हजार रुपये भेज दें, जिन्हें बाद में लौटा दिया जाएगा। इस दौरान वह ओटीपी या कोड से जुड़ी प्रक्रिया का भी सहारा ले रहा है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की

नवाचारों से राजस्व प्रशासन में आया सकारात्मक बदलाव-मुख्यमंत्री साय

- बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका एवं भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की होगी व्यवस्था
- राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीक आधारित समाधान एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों, तकनीक आधारित नवाचारों तथा नागरिकों एवं किसानों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट नीति राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। राजस्व मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी तथा नागरिकों को बिना अनावश्यक कार्यालयीन आवागमन के गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक में डिजिटल किसान किताब एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से सहज रूप से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि उन्हें तहसील अथवा पटवारी कार्यालय जाने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन एवं किसानों के जीवन से जुड़ा विभाग है, इसलिए शासन के सभी सुधारों एवं नवाचारों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध रूप से पहुंचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरबीसी 6-4 की ऑनलाइन व्यवस्था एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसके लागू होने पर आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध होगी। उन्होंने अविवादित फौती नामांतरण की प्रक्रिया पंचायतों के माध्यम से संपादित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर विशेष बल देते हुए सीमांकन प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने तथा समय-सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों की जिला-वार नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नकल शाखा को पूर्णत: ऑनलाइन करने के लिए इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिला एवं तहसील कार्यालयों के महत्वपूर्ण राजस्व अभिलेखों का एकीकृत डिजिटल अभिलेखागार विकसित किया जाएगा।

बारनावापारा अभयारण्य 31 अक्टूबर तक बंद.....

रायपुर। संवाददाता

वन्यजीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बारनावापारा वन्यजीव अभयारण्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। हर वर्ष मानसून के दौरान वन्यजीवों के प्रजनन काल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया जाता है। हालांकि, इस दौरान पर्यटकों को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ने के लिए बलौदाबाजार वनमंडल ने बारनावापारा-सिरपुर पर्यटन सर्किट : द सेक्रेड गारलैंड की शुरुआत की है। इस पहल के माध्यम से राजधानी रायपुर के आसपास स्थित प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को एक पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस पर्यटन सर्किट में सिरपुर, धसकुंड जलप्रपात, तुरतुरिया ईको कल्चरल सेंटर, गिरौदपुरी धाम, सिद्धखोल जलप्रपात, सोनाखान, शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक, देवपुर नेचर कैंप, अचानकपुर का देव हिल्स ईको एथनिक स्टे, कोडार जलाशय सहित कई प्रमुख पर्यटन स्थल शामिल हैं। यहां पर्यटक हरियाली, झरनों, पहाड़ियों, वन क्षेत्र, धार्मिक स्थलों, पुरातात्विक धरोहरों और जनजातीय संस्कृति का अनूठा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। मानसून के मौसम में पूरा क्षेत्र हरियाली से भर जाता है, जिससे इसकी प्राकृतिक सुंदरता और भी बढ़ जाती है। देवपुर नेचर कैंप, देव हिल्स ईको एथनिक स्टे, सिद्धखोल जलप्रपात, तुरतुरिया धाम, धामनी ईको विलेज, धसकुंड फॉल और सिरपुर इस मौसम के प्रमुख आकर्षण होंगे। इस पर्यटन सर्किट को देशभर में पहचान दिलाने के लिए टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंसियों, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और नेचर फोटोग्राफर्स को भी जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार और सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। वनमंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार यह पहल प्रकृति, संस्कृति, विरासत और स्थानीय समुदायों को एक मंच पर लाने का प्रयास है।

बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से प्रदेश में झमाझम बारिश के आसार

रायपुर। संवाददाता

बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब और मानसूनी द्रोणिका के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश ने जोर पकड़ लिया है। मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। राजधानी रायपुर में 154.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि दुर्ग में 181 मिलीमीटर और राजिम में 185.8 मिलीमीटर बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रायपुर में रात भर बारिश हुई है। सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। यह बारिश किसानों के लिए बेहद राहत भरी है। खेतों में पानी जमा होने से धान की बोनी का कार्य तेज हो गया है। हालांकि, प्रदेश के कुछ हिस्सों में अभी भी कम बारिश हुई है। पिछले 36 घंटे से हो लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर रफ्तार से हवाओं ने ने कहर मचाया हैं। कहीं सड़कें बह गई, कहीं लोग बाढ़ के पानी में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला जा रहा हैं। जिलों में नदियां खतरे के निशान के करीब बह रही है। कई एनीकट से ऊपर से पानी बह रहा है। दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि पहले राहत मिलने के आसार कम है। लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश ने निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की भी पोल खोल दी है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सड़के टूट गई हैं, पुल-पुलियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राजनांदगांव के रेलवे ओवर बिज्ञ की सड़क बीचो-बीच फट गई, वहीं जिला अस्पताल में पानी मरीजों के बेड तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने निकले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की एडवाजरी का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है।

बच्चों के चेहरों पर मुस्कान, कर्मचारियों का जन्मदिन बना यादगार-प्रोजेक्ट आओ बाँटें खुशियाँ के तहत शासकीय कर्मचारी बच्चों संग साझा कर रहे हैं खुशियाँ

महिला उत्पीड़न से संबंधित 28 प्रकरणों की हुई सुनवाई

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नायक ने की जनसुनवाई...

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया ने आज जांजगीर-चांपा जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की जनसुनवाई की। डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर यह 410वीं तथा जिले में 12वीं जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कुल 28 प्रकरणों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि मार्च माह में परिवार परामर्श केन्द्र में दोनों पक्षों के बीच सुलह हो

चुकी है। दंपति का 3 वर्ष 6 माह का एक पुत्र है तथा अनावेदक वन रक्षक के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में दोनों अलग मकान लेकर आपसी सामंजस्य से रह रहे हैं। आयोग ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद भविष्य में विवाद नहीं करने की समझाइश दी तथा प्रकरण का निराकरण करते हुए सखी प्रशासिका को दोनों पक्षों की प्रत्येक माह काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए। एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अनावेदकों ने आवेदिका से माफी मांगी। उल्लेखनीय है कि 26 सितम्बर 2024 को आयोग कार्यालय में सुनवाई के दौरान आयोग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई थी, जिसकी शिकायत गोलबाजार थाने में दर्ज कराई गई थी। आयोग के समक्ष अनावेदकों ने उक्त घटना के लिए खेद व्यक्त करते हुए माफी मांगी।

जल जीवन मिशन के ठेकेदारों का रायपुर में प्रदर्शन, 2 हजार करोड़ बकाया भुगतान की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के ठेकेदारों ने लंबित भुगतान को लेकर सोमवार को राजधानी रायपुर स्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के मुख्यालय नीर भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। ठेकेदारों का आरोप है कि काम पूरा हुए दो-दो साल बीत जाने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया गया है, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ठेकेदारों का दावा है कि विभाग पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये का बकाया लंबित है। उनका आरोप है कि जल जीवन मिशन के संचालक लगातार नए-नए नियम लागू कर भुगतान रोक रहे हैं और कई पूर्ण हो चुके कार्यों का हैंडओवर भी नहीं होने दिया जा रहा है। ठेकेदार संघ के प्रदेश अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने बताया कि 8 जून को प्रतिनिधिमंडल ने मिशन संचालक अब्दुल कैशर हक से मुलाकात कर 30 जून तक भुगतान का आश्वासन मिलने पर आंदोलन स्थगित किया था। लेकिन तय समय तक समाधान नहीं हुआ। संघ का दावा है कि आर्थिक तंगी से परेशान तीन ठेकेदारों ने आत्महत्या कर लिया, जिसके बाद आंदोलन का निर्णय लिया गया।

समय पर खाद-बीज ने बढ़ाया अन्नदाताओं का और विश्वास....

रायपुर। जून और जुलाई के शुरुआती दिनों में मानसून की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। आसमान में बादलों की आवाजाही तो थी, लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होने से खेत सूने पड़े थे। खरीफ फसलों की बुआई, धान की रोपाई और बेहतर उत्पादन को लेकर किसान चिंतित थे। हर दिन आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते अन्नदाता अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार पिछले कुछ दिनों से हुई झमाझम बारिश ने किसानों की चिंता को खुशी में बदल दिया। तपती धूप से तपी धरती पर जैसे ही वर्षा की बूंदें बरसीं, केवल मिट्टी ही नहीं महकी, बल्कि किसानों के मन में भी नई उम्मीद और आत्मविश्वास के अंकुर फूट पड़े। मानसून की यह दस्तक केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में नई ऊर्जा, नई आशा और नई शुरुआत का संदेश लेकर आई है। दूर-दूर तक फैले खेतों में अब पानी लबालब दिखाई दे रहा है। गांवों में फिर से चहल-पहल लौट आई है। खेतों में ट्रैक्टरों की गूंज, कृषि यंत्रों की आवाज, धान की रोपाई में जुटे किसान परिवार और प्रकृति का नव श्रृंगार ग्रामीण जीवन की सजीव तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। कहीं खेतों की जुताई अंतिम चरण में है तो कहीं किसान पूरे उत्साह के साथ धान की रोपाई में जुट गए हैं। वर्षा की हर बूंद मानो किसानों की मेहनत को नई शक्ति प्रदान कर रही है। यही वह समय है, जब धरती और अन्नदाता का अटूट रिश्ता सबसे अधिक सजीव दिखाई देता है। किसान पूरे विश्वास के साथ खेतों में उतरता है, क्योंकि उसे पता है

नकटी मामले में कांग्रेस के सभी आरोप निराधार

साय सरकार ने संवेदनशीलता के साथ किया कार्य-केदार

- कांग्रेस भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है : कश्यप
- कांग्रेस शासन में शुरू हुई भूमि आबंटन प्रक्रिया, आज तथ्यों को छिपाकर कर रही राजनीति : केदार कश्यप

रायपुर। संवाददाता

वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि नकटी ग्राम प्रकरण को लेकर कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह निराधार, भ्रामक और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। कांग्रेस जनता के बीच भ्रम फैलाकर सरकार की छवि खराब करने का सुनियोजित प्रयास कर रही है, जबकि इस पूरे मामले की वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई को अच्छी तरह जानती है। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जिस भूमि को लेकर आज कांग्रेस राजनीति कर रही है, उसके आबंटन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2020 से तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी। राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह भूमि हाउसिंग बोर्ड को आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित थी। आबंटन के लिए भूमि चिन्हित होने के बाद वहां लगातार अवैध कब्जे बढ़ते गए और लगभग 3 हेक्टेयर से बढ़कर 15 हेक्टेयर तक अतिक्रमण फैल गया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण

में लगातार विधिसम्मत कार्रवाई करने का प्रयास किया। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कब्जाधारियों के पुनर्वास और व्यवस्थापन के लिए कई बार सहमति बनाने का प्रयास किया गया। कार्रवाई के दौरान भी संवेदनशीलता बरती गई और प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन का प्रयास किया गया। मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के इस आरोप को पूरी तरह असत्य बताया कि नकटी गांव को पूरी तरह उजाड़ दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकटी गांव के 17 वार्डों में से केवल एक वार्ड में, जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था, वहीं कार्रवाई की गई। पूरे गांव को उजाड़े जाने का प्रचार कांग्रेस द्वारा जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि लोगों में भ्रम और आक्रोश पैदा किया जा सके। मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने इस विधिसम्मत प्रशासनिक कार्रवाई को जन आंदोलन का स्वरूप देने का असफल प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित लोगों को भड़काने, धरना-प्रदर्शन कराने और सरकार को बदनाम करने की राजनीति की, लेकिन कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस आज भी इसी प्रकार की भड़काऊ राजनीति में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कार्यकाल को भी याद करना चाहिए। भूपेश बघेल सरकार के समय ग्राम सेरीखेड़ी में लगभग 150 परिवारों को बलपूर्वक हटाया गया था, तब न तो किसी का पुनर्वास किया गया और न ही रहने की कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।

संपादकीय

सरकार फिर ला सकती है नया संविधान संशोधन

पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। देश की राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के मसले पर लंबे समय से बहस चलती रही है, लेकिन अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, ताकि सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। आए दिन संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।इसी संदर्भ में केंद्र सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पांच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है।गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था।इसमें कोई दोराय नहीं कि भारतीय राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का बढ़ता दखल आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर कई बार ऐसे लोग भी चुनकर संसद या विधानसभाओं में आ जाते हैं, जिन पर जघन्य अपराधों में शामिल होने का आरोप होता है। अक्सर सामने आने वाली रिपोर्ट में खासी संख्या में दागी जनप्रतिनिधियों के विधायिका में पहुंचने का ब्योरा होता है, जिस पर सभी दल चिंता जताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट न देने को लेकर किसी के भीतर कोई इच्छाशक्ति नहीं दिखती। दूसरी ओर, चुनाव आयोग भी इस मसले पर कोई स्पष्ट रुख अख्तियार नहीं करता है।इस लिहाज से देखें, तो सार्वजनिक जीवन में जवाबदेही बढ़ाने से लेकर लोकतंत्र में नैतिकता और शुचिता सुनिश्चित किए जाने के लिए एक सख्त नियमन वक्त की जरूरत है। मगर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि नया कानून देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर विपरीत प्रभाव डालने वाला न हो।

भाई-बहन की जोड़ी मोदी-ताकाइची ने रचा इतिहास, हिंद प्रशांत में संतुलन की नई धुरी बने भारत-जापान

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं।

(नीरज कुमार दुबे)

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया।

भारत और जापान ने अपने विशेष सामरिक वैश्विक साझेदारी संबंधों को नई मजबूती देते हुए नई दिल्ली में आज कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के बीच हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता जैसे अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों देशों ने साफ संकेत दिया कि बदलते वैश्विक हालात के बीच भारत और जापान अब केवल आर्थिक साझेदार नहीं, बल्कि एक दूसरे के भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी बनकर उभर रहे हैं।

हम आपको बता दें कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। राष्ट्रपति भवन में उनका भव्य स्वागत किया गया और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा बयान जारी करते हुए संबंधों को और गहरा करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची को अपनी छोटी बहन बताते हुए भारत और जापान के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों का भी उल्लेख किया, विशेषकर जापान के नारा प्रांत से भारत के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया। वहीं ताकाइची ने भी मोदी को अपना बड़े भाई बताया और कहा कि दोनों देशों के संबंध अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग रहा। दोनों देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में संयुक्त वक्तव्य जारी किया और भारतीय तथा जापानी संस्थानों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जापान की सूक्ष्म तकनीकी क्षमता और भारत की सापटवेयर विशेषज्ञता का मेल वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को नई दिशा देगा। यह सहयोग केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में तकनीकी प्रतिस्पर्धा तेजी से भू राजनीतिक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है।

रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत और जापान ने अपने पहले संयुक्त रक्षा विकास परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना प्रणाली यूनिकॉर्न के सह विकास से संबंधित है। इस समझौते को हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि दोनों देश क्वॉड समूह के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। चीन की बढ़ती समुद्री आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर से लेकर पूर्वी चीन सागर तक बदलते सामरिक समीकरणों के बीच यह रक्षा सहयोग विशेष महत्व रखता है।

साथ ही भारत और जापान ने ऊर्जा सुरक्षा तथा आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताई। सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज, धातु और उर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए साझा रूपरेखा तैयार की जाएगी। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार व्यवस्था पर भी चर्चा की, जिसके तहत रुपये और येन में सीधे व्यापार की संभावना पर काम होगा। इससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी।

साथ ही जापान ने अगले दस वर्षों में भारत में दस ट्रिलियन येन निवेश करने की घोषणा दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाएगी। वर्तमान में जापान भारत के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन रेल परियोजना सहित कई आधारभूत ढांचा योजनाओं में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों देशों के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार 27.5 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। जापान की प्रधानमंत्री के साथ आया बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी इस बात का स्पष्ट संकेत था कि टोक्यो भारत में निवेश बढ़ाने जा रहा है।

साथ ही दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली है। औषधि, चिकित्सा उपकरण और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों के माध्यम से दोनों देशों ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की व्यापक उत्पादन क्षमता और जापान की गुणवत्ता आधारित तकनीक मिलकर विश्व को सस्ती और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। इसके साथ ही भारत जापान जैव गैस पहल के अंतर्गत भारत में एक हजार जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

देखा जाये तो यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। चीन की सैन्य सक्रियता, आपूर्ति श्रृंखलाओं पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारत और जापान को और करीब ला दिया है। अमेरिका की विश्वसनीयता को लेकर उठते सवालों के बीच टोक्यो अब नई दिल्ली को अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारों में देख रहा है। भारत भी जापान को केवल निवेशक नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामरिक सहयोगी के रूप में देख रहा है।

हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच गहरे व्यक्तिगत संबंधों ने भी इस साझेदारी को मजबूती दी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी की जापान यात्राओं से शुरू हुआ यह संबंध अब व्यापक सामरिक साझेदारी का रूप ले चुका है। वर्तमान वार्ता ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले वर्षों में भारत जापान संबंध एशिया की सबसे निर्णायक रणनीतिक धुरी बन सकते हैं।

देखा जाये तो भारत और जापान की बढ़ती दोस्ती का प्रभाव केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे एशिया और वैश्विक शक्ति संतुलन पर दिखाई देगा। लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सहयोग और सामरिक विश्वास पर आधारित यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और शांति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। चीन की बढ़ती आक्रामकता, वैश्विक आपूर्ति संकट और बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और जापान का साथ आना एशिया में एक नए रणनीतिक संतुलन का संकेत माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी न केवल व्यापार, तकनीक और रक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी, बल्कि विश्व राजनीति में भी एक भरोसेमंद और स्थिर शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकती है।(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

आत्मनिर्भर ग्राम पंचायतों का सपना कितना व्यावहारिक? सबसे बड़ी चुनौती आय नहीं, संसाधनों की है

(अमरपाल सिंह वर्मा)

तमाम समस्याओं के बावजूद पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, क्योंकि पंचायतों की आर्थिक मजबूती के बिना वास्तविक विकेंद्रीकरण संभव नहीं है।सरकार ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। इसके लिए हाल में जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का मानना है कि देश में बदलाव की असली शुरुआत गांवों से ही संभव है। इसी सोच के तहत अब ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जा रहा है। इसके पीछे तर्क है कि यदि पंचायतें अपने स्रोतों से आय अर्जित करेंगी, तो वे अपने क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार सड़क, पेयजल, सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च कर सकेंगी। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और सरकारी अनुदानों पर निर्भरता कम होगी। सरकार का यह भी मानना है कि मजबूत और आत्मनिर्भर पंचायतें ही विकसित भारत के सपने को साकार कर सकती हैं, लेकिन क्या पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना वास्तव में इतना आसान है? यह सवाल इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आजादी के बाद से गांवों के विकास की जो व्यवस्था बनी, उसमें पंचायतों की भूमिका तो बढ़ती गई, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत उतनी नहीं बढ़ पाई। पंचायतों के कामकाज का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर रहा है। आज भी अधिकांश पंचायतें स्वयं की आय के बजाय सरकारी योजनाओं और अनुदानों पर अधिक निर्भर हैं। ऐसे में पंचायतों से आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की अपेक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकार का कहना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब केवल पैसा जुटाना नहीं है। सरकारी दस्तावेजों में आर्थिक आत्मनिर्भरता को केवल राजस्व जुटाने तक सीमित नहीं माना गया है। इसके पीछे सोच यह है कि पंचायतों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करने और फैसले लेने की अधिक स्वतंत्रता मिले। यदि पंचायतों की अपनी आय होगी, तो वे यह तय कर पाएंगी कि गांव में सबसे जरूरी काम टूटी सड़क बनवाना है या पेयजल व्यवस्था सुधारना, सार्वजनिक भवनों की मरम्मत कराना अथवा सफाई व्यवस्था को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पिछले कुछ वर्षों में ग्राम पंचायतों की भूमिका बदली है। वे अब केवल योजनाओं को लागू करने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं, बल्कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार हैं। इसके बावजूद पंचायतों की वित्तीय निर्भरता की समस्या यथावत बनी हुई है। पंचायतों की आत्मनिर्भरता की वास्तविक स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हाल में दिल्ली में दिए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में देश भर की केवल चार पंचायतों को ही 'आत्मनिर्भर आधारभूत संरचना' श्रेणी में सम्मानित किया गया है। सर्वविदित है कि देश की अधिकांश ग्राम पंचायतों की आय का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों से आता है। अपने स्तर पर राजस्व जुटाने का अधिकार होने के बावजूद पंचायतों ने इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं की है। सवाल है कि पंचायतें आय बढ़ाएंगी कैसे? कानूनी रूप से पंचायतों के पास कई अधिकार हैं। वे भवन कर लगा सकती हैं, सफाई कर और पथ-प्रकाश कर वसूल सकती हैं। यहां तक कि जल उपयोग शुल्क ले सकती हैं। गांवों में लगने वाले हाट-बाजार, मेले, सामुदायिक भवनों, दुकानों के किराए और अन्य स्थानीय संसाधनों से भी आय अर्जित कर सकती हैं। लेकिन कागजों पर दिखाई देने वाले ये स्रोत यथार्थ के धरातल पर उतने प्रभावी नहीं होते। गांवों में कर वसूली का विषय केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी है। सरपंच और वार्ड पंच उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं, जिनसे उन्हें कर वसूलना होता है। ऐसे में कर लगाने या वसूली करने पर प्रायः विरोध का सामना करना पड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से बड़े राज्य राजस्थान पर नजर डालें, तो चुनौती और स्पष्ट दिखाई देती है। यहां की अधिकांश पंचायतों के पास न तो बड़े बाजार है, न औद्योगिक इकाइयां और न ही पर्यटन से जुड़ी आय। ज्यादातर जिलों की पंचायतें आज भी मुख्य रूप से कृषि और सरकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। राज्य की अधिकांश ग्राम पंचायतों के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं, जिनसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सके। कुछ पंचायतों के पास बाजार, व्यावसायिक गतिविधियां, पर्यटन स्थल या आय के अन्य स्रोत मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश पंचायतें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। वहां स्थानीय आय बढ़ाने की संभावनाएं सीमित हैं। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या सभी पंचायतों को एक ही पैमाने से मापा जा सकता है? क्या सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र की पंचायत और किसी विकसित कस्बे से सटी पंचायत की स्थिति एक समान है? क्या आर्थिक रूप से कमजोर गांवों से भी वही अपेक्षा जायज है, जो अपेक्षाकृत संपन्न क्षेत्रों से की जाती है? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है, क्योंकि केवल लक्ष्य तय कर देने से उपलब्धियां हासिल कर पाना संभव नहीं होता।

बढ़ता कद, बढ़ते हमले और कमजोर पड़ता सुरक्षा कवच

क्या डॉ. मोहन यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष है या अपना संचार तंत्र?

कृष्णमोहन झा/

राजनीति का एक अलिखित नियम है–जैसे-जैसे किसी नेता का कद बढ़ता है, वैसे-वैसे उसके विरोधियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। जब तक कोई नेता केवल अपने प्रदेश तक सीमित रहता है, उसके विरोध भी सीमित रहते हैं। लेकिन जैसे ही वह राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपयोगिता और प्रभाव सिद्ध करने लगता है, उसके हर कदम, हर निर्णय और हर गतिविधि का राजनीतिक विश्लेषण शुरू हो जाता है। यही स्थिति आज मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संदर्भ में दिखाई दे रही है।

लगभग ढाई वर्ष पूर्व जब डॉ. मोहन यादव को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब राजनीतिक विश्लेषकों के एक बड़े वर्ग ने इसे एक अप्रत्याशित निर्णय माना था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। इन ढाई वर्षों में उन्होंने केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनावों में उनकी सक्रिय भागीदारी इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें केवल मध्यप्रदेश तक सीमित नेता के रूप में नहीं देख रहा।

विशेष रूप से बिहार में यादव बहुल क्षेत्रों में उनकी सभाओं और संपर्क अभियानों को भाजपा ने रणनीतिक महत्व दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का उद्देश्य उन सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाना था, जो परंपरागत रूप से उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर माने जाते रहे हैं। चाहे इसका पूरा श्रेय किसी एक नेता को न दिया जा सके, लेकिन यह स्पष्ट है कि डॉ. मोहन यादव को पार्टी ने इस सामाजिक विस्तार की रणनीति में एक प्रमुख चेहरा बनाया। इससे उनका राजनीतिक कद स्वाभाविक रूप से बढ़ा है।

यहीं से राजनीति का दूसरा अध्याय शुरू होता है।

भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि जब कोई नेता तेजी से उभरता है, तो उसके सामने चुनौतियां भी कई दिशाओं से आने लगती हैं। विपक्ष उसके हर निर्णय पर सवाल उठाता है, मीडिया उसकी

गतिविधियों की अधिक बारीकी से जांच करता है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का दायरा भी व्यापक हो जाता है। यह किसी एक दल की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति की स्वाभाविक प्रक्रिया है।

हाल के दिनों में एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट और उसके बाद कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों ने इसी बहस को जन्म दिया। विपक्ष ने मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया, जबकि भाजपा ने उन आरोपों का तथ्यों के साथ खंडन किया। लोकतंत्र में यह सब असामान्य नहीं है। असली प्रश्न कहीं और है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आरोप नहीं, बल्कि संचार का अभाव रहा। यदि किसी समाचार के संबंध में समय रहते मुख्यमंत्री कार्यालय या सरकार की ओर से अधिकृत, तथ्यात्मक और विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आ जाती, तो संभवतः राजनीतिक विमर्श का स्वरूप अलग होता। राजनीति में कई बार तथ्य देर से सामने आने पर उनका प्रभाव भी कम हो जाता है।

यहीं मुझे डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती दिखाई देती है।

ढाई वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर अपनी कार्यशैली स्थापित की, निवेश को गति देने का प्रयास किया, धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा दी तथा राष्ट्रीय नेतृत्व का विश्वास भी अर्जित किया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे अभी तक ऐसा राजनीतिक और संचार सुरक्षा कवच तैयार नहीं कर पाए हैं, जो संकट के समय तथ्यों के साथ तत्काल सामने आ सके।

आज की राजनीति केवल विकास कार्यों से नहीं चलती, बल्कि धारणा (ब्व्हृव्श्च्ह्ढ्शठ्ठ)से भी संचालित होती है। यदि आप अपना पक्ष समय पर नहीं रखते, तो विरोधी अपना पक्ष स्थापित कर देते हैं। बाद में दिया गया स्पष्टीकरण अक्सर पहले से बनी धारणा को पूरी तरह बदल नहीं पाता।

यह केवल डॉ. मोहन यादव की समस्या नहीं है। आधुनिक राजनीति का यह नया यथार्थ है। अब चुनाव केवल मंचों पर नहीं, बल्कि मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जनधारणा के स्तर पर भी लड़े जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के पास जितनी मजबूत प्रशासनिक टीम होनी चाहिए, उतनी ही सक्षम राजनीतिक, कानूनी और मीडिया प्रतिक्रिया देने वाली टीम भी आवश्यक है।

यह भी उतना ही सत्य है कि किसी भी लोकप्रिय नेता पर आरोप लगेंगे। विपक्ष का काम सवाल उठाना है और मीडिया का दायित्व भी प्रश्न पूछना है। लेकिन किसी भी जननेता की सबसे बड़ी शक्ति उसकी पारदर्शिता, विश्वसनीयता और समय पर संवाद होती है। यही गुण राजनीतिक हमलों की धार को कम करते हैं।

डॉ. मोहन यादव के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं है। विपक्ष लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है और अपनी भूमिका निभाता रहेगा। वास्तविक चुनौती यह है कि क्या उनका राजनीतिक तंत्र उनके बढ़ते राष्ट्रीय कद के अनुरूप स्वयं को विकसित कर पा रहा है? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में ऐसा त्वरित संचार तंत्र है, जो किसी भी विवाद पर तुरंत तथ्य प्रस्तुत कर सके? क्या ऐसी विश्वसनीय टीम तैयार हो चुकी है, जो राजनीतिक और मीडिया दोनों मोर्चों पर प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रख सके?

यदि इन प्रश्नों पर समय रहते गंभीरता से विचार किया गया, तो डॉ. मोहन यादव का राजनीतिक भविष्य और अधिक मजबूत हो सकता है। लेकिन यदि संवाद का यही शून्य बना रहा, तो भविष्य में भी उपलब्धियों से अधिक विवाद चर्चा का विषय बन सकते हैं।

राजनीति में विरोधी उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, जितना कई बार *समय पर न बोला गया सत्य** पहुंचा देता है। बड़े नेताओं की पहचान केवल उनकी लोकप्रियता से नहीं होती; उनकी पहचान इस बात से भी होती है कि वे संकट के समय कितनी पारदर्शिता, आत्मविश्वास और तत्परता से जनता के सामने आते हैं।

डॉ. मोहन यादव के सामने यह अवसर भी है और चुनौती भी। यदि वे अपनी प्रशासनिक उपलब्धियों के समान ही अपने राजनीतिक एवं संचार तंत्र को भी सुदृढ़ कर लेते हैं, तो न केवल मध्यप्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। क्योंकि आज के दौर में नेतृत्व केवल निर्णयों से नहीं, बल्कि संवाद से भी स्थापित होता है।

शासकीय उच्चरत माध्यमिक विद्यालय मालगांव, जिला-कोण्डागांव में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

विद्यार्थियों को संवैधानिक अधिकरों, कर्तव्यों एवं नि:शुल्क विधिक सहायता की दी गई जानकारी

कोण्डागांव। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव खिलावन राम रिंगरी' के मार्गदर्शन एवं 'सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय' की उपस्थिति में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मालगांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 'प्रतिधारक अधिवक्ता सुरेन्द्र भट्ट एवं अधिकार मित्र रंजन कुमार बैघ, लोकेश कुमार यादव' ने छात्र-छात्राओं को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, किशोर न्याय, महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून, साइबर अपराध से बचाव सोशल मीडिया से सुरक्षित उपयोग तथा नशामुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही विद्यार्थियों को बताया गया कि विधिक जागरूकता का उद्देश्य केवल कानूनों की जानकारी देना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाकर न्याय तक उसकी सहज पहुँच सुनिश्चित करना भी है। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न विधिक विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे, जिनका सरल एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समाधान किया गया। साथ ही विद्यार्थियों से कानून का सम्मान करने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने, बाल विवाह एवं नशे जैसी सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध जागरूकता फैलाने तथा अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की सहभागिता रही। अंत में विद्यालय परिवार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस उपयोगी एवं जनहितकारी कार्यक्रम की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के नियमित आयोजन की अपेक्षा व्यक्त की।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइ, डॉ.ए.वी. पॉब्लिक स्कूल, किरंदुल द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित

किरंदुल। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई डीएवी पब्लिक स्कूल किरंदुल द्वारा मंगलवार विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा हरित वातावरण के निर्माण का संदेश देना था। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य एस के श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी के पी सिन्हा, शिक्षिका धरती वर्मा, शिक्षक ए. के. सोनी, लिपिक संजय मंडल, गजेंद्र झा तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। प्राचार्य एस के श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों एवं स्वयंसेवकों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि वृक्ष पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु तथा भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थितजनों एवं एनएसएस स्वयंसेवकों ने पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लिया तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति निरंतर जागरूक रहने का संदेश दिया।

दीदी के गोठ' रेडियो कार्यक्रम का एक वर्ष पूर्ण, 09 जुलाई को होगा वृहद आयोजन

कोंडागांव। महिला सशक्तिकरण, जनसंवाद तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित 'दीदी के गोठ' रेडियो कार्यक्रम के सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 09 जुलाई को राज्यभर में वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम, क्लस्टर, विकासखंड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाएगा। इस अवसर पर महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्थानीय नागरिकों की सक्रिय सहभागिता रहेगी। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 'दीदी के गोठ' कार्यक्रम ने पिछले एक वर्ष में महिलाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं के समाधान तथा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित यह वृहद कार्यक्रम महिलाओं के आत्मविश्वास, सहभागिता और सशक्तिकरण को नई मजबूती प्रदान करेगा।

जिला अधिवक्ता संघ चुनाव दीपक ठाकुर लगातार दूसरी बार बने अध्यक्ष

कोंडागांव। जिला अधिवक्ता संघ कोंडागांव वर्ष 2026 का चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस बार केवल अध्यक्ष पद के लिए मतदान कराया गया, जबकि अन्य सभी पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता दीपक ठाकुर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा को 51 मतों के अंतर से पराजित करते हुए लगातार दूसरी बार जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया। निर्वाचन परिणाम के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए कुल 83 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें अधिवक्ता दीपक ठाकुर को 62 मत प्राप्त हुए, जबकि अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा को 11 मत मिले। इस प्रकार दीपक ठाकुर ने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज कर दोबारा संघ की कमान संभाली। परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उनकी टीम का स्वागत कर उन्हें बधाई दी। चुनाव में दीपक ठाकुर के पैनल के सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। उपाध्यक्ष पद पर अधिवक्ता नरेंद्र देवांगन, सचिव पद पर सगा राम कोर्राम, सह सचिव पद पर निशा वासनिकर, कोषाध्यक्ष पद पर नरेश नाइक, क्रीड़ा सचिव पद पर नितेश जैन तथा कार्यकारिणी सदस्य के रूप में गोपाल दीक्षित, संजय शार्दुल, गौरव जैन और प्रशांत दत्ता निर्विरोध चुने गए। वहीं महिला उपाध्यक्ष, महिला ग्रंथपाल, महिला कार्यकारिणी सदस्य तथा सांस्कृतिक सचिव के रिक्त पदों पर संघ के प्रावधानों के अनुसार बाद में मनोनयन किया जाएगा। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक ठाकुर एवं सभी पदाधिकारियों ने अधिवक्ता संघ के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। दीपक ठाकुर ने कहा कि अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा तथा उनके हितों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रयास का संघ पूरी मजबूती से विरोध करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आमजन को न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से कोण्डागांव में उपभोक्ता फोरम एवं श्रम न्यायालय की लिंक कोर्ट की स्थापना के लिए पूर्व कार्यकाल में शुरू किए गए प्रयासों को अब और अधिक गति देकर उन्हें अंतिम परिणाम तक पहुंचाया जाएगा। संघ के पूर्व सह सचिव एवं नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता गौरव जैन ने कहा कि यह जीत पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों और अधिवक्ताओं के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं ने दीपक ठाकुर के नेतृत्व पर दोबारा भरोसा जताया है, जिसके लिए वे सभी मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जिला अधिवक्ता संघ आगे भी अधिवक्ता हितों के साथ-साथ जनहित के मुद्दों पर सक्रिय और प्रतिबद्ध रहेगा।

दंतेवाड़ा में लॉ कॉलेज की मांग, विधायक को सौंपा ज्ञापन

दंतेवाड़ा। जिले में विधि महाविद्यालय (एलएलबी) शुरू कराने की मांग एक बार फिर उठी है। भाजपा सोशल मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह ठाकुर ने सोमवार को विधायक चैतराम अटामी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि दंतेवाड़ा में लॉ कॉलेज नहीं होने से दक्षिण बस्तर के विद्यार्थियों को कानून की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है।

ज्ञापन में बताया गया है कि दंतेवाड़ा शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहां बीजापुर और सुकमा जिले से भी बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन विधि शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में दंतेवाड़ा में विधि महाविद्यालय शुरू करने की दिशा में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रवेश प्रक्रिया जैसी तैयारियां हुई थीं, लेकिन आवश्यक मान्यताओं के अभाव में यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद से भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। राजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि यदि बार कार्उंसिल ऑफइंडिया के निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाए तो जिले में विधि महाविद्यालय का संचालन शुरू किया जा सकता है। इससे दंतेवाड़ा के साथ बीजापुर और सुकमा के विद्यार्थियों को भी स्थानीय स्तर पर कानून की पढ़ाई का अवसर मिलेगा।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती

किरंदुल। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती सोमवार को किरंदुल मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता एल्डरमैन संजीव दास ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। उन्होंने 'एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे' का नारा देकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने अपने पिता 'बंगाल टाइगर' के नाम से प्रसिद्ध आशुतोष मुखर्जी से राष्ट्रसेवा, शिक्षा और सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा लिया।आज डॉ. मुखर्जी के दिखाए मार्ग पर चलकर ही देश सशक्त हो रहा है। इस अवसर पर किरंदुल भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सोढ़ी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे वैचारिक अधिष्ठान और प्रेरणापुंज हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर डॉ. मुखर्जी के अखंड भारत के सपने को साकार किया है। किरंदुल मंडल का एक-एक कार्यकर्ता उनके राष्ट्रवाद के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है। उनकी जयंती पर हम सभी देशहित में निरंतर कार्य करने का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान किरंदुल मंडल अध्यक्ष विजय सोढ़ी आर सी नाहक शैलेंद्र सिंह विक्रम नाहक अतुल सिंह प्रकाश जैन प्रेमशिला मिश्रा भावना सक्सेना संजीव दास राजेश वेपरल विकास स्वामी मनीकुट्टन नायर अनु अंकम्मा जोशना सवाई अंजली शर्मा राजेश्वरी सुषमा साहू सविता पिंकी बनमली हरिजन पासवान आदि मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के पदचिह्नों पर चलने और उनके विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

पेंटा में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न

किरंदुल। विकासखंड कुआकोंडा के ग्राम पेंटा में सोमवार विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास, उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवप्रवेशी बच्चों का स्वागत करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, मेधावी विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित करना तथा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और संस्कार से जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक चैतराम अटामी, अध्यक्ष जिला पंचायत नंदलाल मुड़ामी एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की पूजा-अर्चना, दीप प्रज्वलन एवं पौधरोपण के साथ किया गया। इसके पश्चात नवप्रवेशी बच्चों का तिलक-चंदन और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया और उन्हें नियमित अध्ययन, अनुशासन,संस्कार एवं परिश्रम से अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया गया। पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल था और बच्चों के चेहरों पर नई शैक्षणिक यात्रा को लेकर स्पष्ट उत्साह दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत में विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रमोद भदौरिया ने मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, प्राचार्यों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, पालकों एवं सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव केवल विद्यालय में प्रवेश कराने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, उनमें सीखने की रुचि बढ़ाने और समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर पर विगत शैक्षणिक सत्र में कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति-पत्र और मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया।

नेत्रोत्सव से लेकर 24 जुलाई के बहुड़ा गोंचा तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया गया

गोंचा महापर्व की तैयारियों में जुटे युवा, जगन्नाथ मंदिर में बनी आयोजन की रूपरेखा

जगदलपुर । बस्तर के प्रसिद्ध गोंचा महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के युवाओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापर्व के दौरान होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 15 जुलाई को होने वाले नेत्रोत्सव से लेकर 24 जुलाई के बहुड़ा गोंचा तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया गया। रथयात्रा, अमनिया भोग, छप्पन भोग, श्रद्धालुओं के लिए सेवा व्यवस्था, पूजा-अर्चना तथा अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए युवाओं ने कई सुझाव दिए। इन सुझावों को आयोजन की कार्ययोजना में शामिल करने पर सहमति बनी। बैठक में आशु आचार्य ने कहा कि गोंचा महापर्व बस्तर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का प्रमुख उत्सव है। इसकी गरिमा बनाए रखने और आयोजन को सफल बनाने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवाओं का उत्साह और सेवा भाव इस बार महापर्व को और अधिक व्यवस्थित एवं भव्य बनाने में अहम योगदान देगा। बैठक के दौरान समाज के युवाओं ने आयोजन की विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने का संकल्प भी लिया। समाज की ओर से सभी सहभागी युवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सहयोग और समर्पण की सराहना की गई। बैठक में मुरली मनमोहन कवि, जशवंत जोशी, धर्मेंद्र पांडे, पुनीत पांडे, डी.के. पांडे, मोहन जोशी, कुलेश जोशी, प्रकाश पांडे, रोहित पांडे, कौशल पांडे, विपिन पानिग्रही, कर्तव्य आचार्य, शुभम आचार्य सहित 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

जिले के समस्त शिक्षण संस्थान एवं छात्रावास घोषित हुए ड्रग फ्री जोन

नशे की लत से दूर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी

नारायणपुर। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थानों तथा छात्रावासों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों के परिपालन में जिला शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि इस क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री अथवा इससे संबंधित गतिविधियां पाई जाती हैं तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नशामुक्त भारत अभियान के तहत सभी संस्था प्रमुखों को अपने शिक्षण संस्थान एवं छात्रावास के आसपास 500 मीटर की परिधि में सतत निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटस्थ पुलिस थाना एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न गतिविधियों एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। जारी निर्देशों के अनुसार इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन एनसीओआरडी के तहत स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग तथा सामुदायिक संगठनों के समन्वय से किया जाएगा, ताकि शिक्षण संस्थानों के आसपास पूर्णतः सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि नारायणपुर जिले को नशामुक्त बनाने के लिए शिक्षा विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। युवा पीढ़ी को नशे की लत से दूर रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधन, प्राचार्यों, शिक्षकों एवं छात्रावास अधीक्षकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने जिलेवासियों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि कहीं भी मादक पदार्थों के अवैध क्रय-विक्रय अथवा नशे से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन अथवा निकटस्थ पुलिस थाना को दें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

संक्षिप्त समाचार

महापौर ने किया जलभराव क्षेत्रों का मैराथन दौरा मौके पर कराई जल की निकासी

कोरबा। महापौर संजू देवी राजपूत ने शहर में भारी वर्षा के बीच निगम क्षेत्र के कोरबा, टीपी नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकरनगर, बालको, दर्री, जोनअंतर्गत वार्ड एवं बस्तियों का सघन दौरा किया, उन्होंने वार्ड पार्षदों व अधिकारियों के साथ जल भराव क्षेत्रों का दौरा करते हुए जल भराव वाले क्षेत्र से पानी की तत्काल निकासी करने, वर्षा की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए जल भराव की समस्या से निपटने, सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। कोरबा शहर में रविवार से लगातार बारिश का क्रम जारी है, भारी वर्षा के परिणाम स्वरूप शहर में अनेक स्थानों पर जल भराव की समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने सोमवार को सुबह से ही निगम क्षेत्र के कोरबा, टीपी नगर, कोसाबाड़ी, रविशंकर नगर, बालको व दर्री जोन अतर्गत विभिन्न बस्तियों व वार्डों में जल भराव वाले क्षेत्रो का लगातार दौरा कर स्थित का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न जल भराव वाले क्षेत्र में जल की तत्काल निकासी किए जाने के निर्देश देने के साथ ही अनेक स्थलों पर मौके पर ही आवश्यक संसाधन व मशीनरी बुलाकर जल की निकासी कराई। महापौर राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निगम अधिकारी कर्मचारियों की अपनी टीम व आवश्यक संसाधनों के साथ निगम क्षेत्र के सभी वार्ड बस्तियों में लगातार भ्रमण करें तथा भारी वर्षा से उत्पन्न जल भराव की स्थिति पर सतर्क नजर रखें, जहां कहीं पर भी जल भराव की स्थिति पैदा होती है वहाँ युद्ध स्तर पर कार्यवाही कर जल की निकासी कराए, ताकि आम नागरिकों को जल भराव की समस्या से त्वरित राहत पहुंचाई जा सके। जोनवार टीमें स्थिति पर रख रही नजर - महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत व आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय के मार्गदर्शन में नगर निगम कोरबा की टीमें निगम के सभी जोन में लगातार भ्रमण करते हुए स्थिति पर नजर रख रही है तथा प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव की समस्या के तुरंत समाधान के लिए पंपों के माध्यम से पानी की निकासी तथा अन्य संबंधित कार्य तेजी के साथ किये जा रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे जल भराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही न करें तथा किसी भी आपातकालीन स्थिति की जानकारी तत्काल नगर निगम के अधिकारियों को दें ताकि जल निकासी के साथ ही आवश्यक राहत व बचाव कार्य त्वरित रूप से किया जा सके।

बारिश के मौसम में करंट से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने विद्युत कंपनी ने जारी की एडवाइजरी

कोरबा। बारिश का मौसम शुरू होते ही विद्युत करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। बिजली के खंभों, एचटी लाइनों, टूटे तारों तथा विद्युत उपकरणों के संपर्क में आने से हर वर्ष कई हादसे होते हैं, जिनमें कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। इन दुर्घटनाओं से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिलासपुर क्षेत्र ने आम नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी जारी करते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कंपनी ने कहा है कि थोड़ी-सी लापरवाही भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों एवं अन्य विद्युत उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें। यदि आंधी-तूफान या बारिश के दौरान बिजली के खंभे, तार अथवा अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त दिखाई दें, तो इसकी सूचना तत्काल कंपनी के टोल-फ्री नंबर 1912, मोर बिजली ऐप अथवा निकटतम वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में दें। बारिश के दौरान बिजली के खंभों, तारों और ट्रांसफार्मरों से दूर रहें। जहां विद्युत तार या उपकरण मौजूद हों, वहां पानी में करंट फैलने की संभावना रहती है। ऐसे स्थानों पर पानी में चलने या तैरने से बचें। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हाथ-पैर सूखे रखें तथा रबर या प्लास्टिक के जूते-चप्पलों का उपयोग करें। विभाग ने बताया कि बारिश से पहले सभी फीडरों, ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत लाइनों का निरीक्षण और आवश्यक रखरखाव किया जा चुका है। इसके बावजूद नागरिकों की सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। घरों, खेतों एवं अन्य स्थानों पर केवल गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपकरणों का उपयोग करें। खेत या बाड़ी की बाड़ तथा कंटीले तारों में बिजली प्रवाहित न करें। यह अवैध होने के साथ-साथ जानलेवा भी हो सकता है तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। विद्युत लाइनों, ट्रांसफार्मरों या अन्य उपकरणों में खराबी आने पर स्वयं सुधार करने का प्रयास न करें। बिजली की लाइनों के नीचे अथवा उनके समीप स्थायी या अस्थायी निर्माण न करें तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यदि कोई विद्युत तार टूटकर जमीन, नदी, नाले या तालाब में गिरा हुआ मिले, तो उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखें और तत्काल संबंधित लाइनमैन, कनिष्ठ अभियंता अथवा टोल-फ्री नंबर 1912 पर सूचना देकर विद्युत प्रवाह बंद कराएं। बिजली की लाइनों से हुकिंग कर अनाधिकृत रूप से बिजली का उपयोग न करें। कपड़े सुखाने के लिए बिजली के खंभों या स्टे वायर का उपयोग न करें तथा कपड़े सुखाने वाले तार को विद्युत लाइनों से पर्याप्त दूरी पर रखें। अस्थायी विद्युत कनेक्शन के लिए कटे-फटे तारों का उपयोग न करें तथा बच्चों को विद्युत उपकरणों एवं लाइनों के आसपास खेलने से रोकें।

एसईसीएल में निवारक सतर्कता एवं सुशासन पर मंथन

केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शदाता श्री राजीव वर्मा ने प्रभावी सतर्कता प्रशासन पर साझा किए गए विचार...

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मुख्यालय में सोमवार को निवारक सतर्कता, शिकायत निवारण एवं सतर्कता प्रशासन विषय पर संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के परामर्शदाता श्री राजीव वर्मा ने कहा कि निवारक सतर्कता का उद्देश्य केवल अनियमितताओं की जांच करना या दंड देना नहीं, बल्कि ऐसी पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम हो। उन्होंने शिकायतों के निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण, जोखिम आधारित सतर्कता व्यवस्था तथा सर्वोत्तम प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में एसईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री अजय कुमार जायसवाल, निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री एन. फ्रैंकलिन जयकुमार,

निदेशक (मानव संसाधन) श्री बिरंची दास, निदेशक (वित्त) श्री दरला सुनील कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन, निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) श्री रमेश चंद्र महापात्र, सहित विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एसईसीएल के सभी संचालन क्षेत्रों के अधिकारी एवं कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरदार वल्लभभाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन ने कहा, पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही एसईसीएल की कार्यसंस्कृति के मूल आधार हैं। निवारक सतर्कता प्रभावी प्रशासन का महत्वपूर्ण स्तंभ है और ऐसे संवाद संगठन में सत्यनिष्ठा की संस्कृति को और सुदृढ़ करते हैं। स्वागत उद्बोधन में मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री हिमांशु जैन ने कहा कि एसईसीएल में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों जैसे डिजीकोल तथा ऑनलाइन पोर्टल जैसी व्यवस्थाएं निर्णय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के साथ-साथ निवारक सतर्कता को भी मजबूत कर रही हैं। कार्यक्रम के दौरान श्री हरीश दुहन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा संकल्प दिलाया। सत्र के अंत में आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने सतर्कता प्रशासन, शिकायत निवारण एवं अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका श्री राजीव वर्मा ने व्यावहारिक उदाहरणों सहित उत्तर दिया। इससे पूर्व श्री राजीव वर्मा ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री हरीश दुहन से शिष्टाचार भेंट की। इसके पश्चात उनकी अध्यक्षता में विभागाध्यक्षों एवं सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सतर्कता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।

व्हाट्सएप पर मिला टिकट नहीं आया काम, यात्री को भरना पड़ा जुर्माना......

डिजिटल टिकट के नियम जानना भी है जरूरी

बिलासपुर। भैया, जल्दी से रायपुर तक का टिकट बना दो...। कोरबा से रायपुर की यात्रा कर रही कुमारी अंकिता (बदला हुआ नाम) ने जैसे ही ट्रेन में टिकट जांच कर्मचारी (टीटीई) को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने तत्काल अपने भाई को फोन किया। भाई ने ऋद्धद्यहुद्ध क्षक्ष के माध्यम से कोरबा से रायपुर तक का अनारक्षित टिकट बनाकर उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप से उनके मोबाइल पर भेज दिया। अंकिता को लगा कि अब समस्या टल जाएगी, लेकिन रेलवे के नियम कुछ और ही कहते हैं। गाड़ी संख्या 18517 कोरबाङ्कविशाखापत्तनम लिंक एक्सप्रेस कोरबा स्टेशन से सायं 4:10 बजे प्रस्थान कर चुकी थी। टिकट जांच के दौरान अंकिता द्वारा प्रस्तुत टिकट का परीक्षण करने पर पाया गया कि वह टिकट सायं 4:45 बजे जारी किया गया था तथा उसका केवल स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाया जा रहा था। रेलवे के प्रचलित नियमों के अनुसार ऐसा स्क्रीनशॉट वैध यात्रा प्राधिकार नहीं माना जाता। परिणाम स्वरूप टिकट जांच कर्मचारी ने टिकट को अमान्य घोषित करते हुए नियमानुसार

जुर्माना वसूल किया। पूछताछ के दौरान अंकिता ने बताया कि उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि मोबाइल से बनाए गए अनारक्षित टिकट की वैधता के लिए टिकट उसी मोबाइल फोन में उपलब्ध होना चाहिए, जिसमें ऋद्धद्यहुद्ध क्षक्ष पंजीकृत है और जिससे टिकट बनाया गया हो। केवल व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त टिकट दिखाकर यात्रा करना नियमों के अनुरूप नहीं है। इस घटना के माध्यम से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सभी यात्रियों को जागरूक करना चाहता है कि डिजिटल टिकट का उपयोग करते समय रेलवे के निर्धारित नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

सिम्स की बदहाल व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त एआई से शपथ पत्र तैयार करने पर जताई नाराजगी....

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान में बदहाल व्यवस्थाओं और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर कड़ी नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने कहा कि शपथ पत्र के कई हिस्सों में एक जैसी बातें दोहराई गई हैं, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ङ्क) की मदद से तैयार किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि दस्तावेज भले ही व्यवस्थित और आकर्षक दिखता हो, लेकिन इससे अस्पताल की जमीनी हकीकत नहीं बदल जाती। उन्होंने कहा कि यदि छ्ङ्क्ष्ख की व्यवस्थाएं संतोषजनक होतीं तो मामला हाईकोर्ट तक

नहीं पहुंचता। सरकार और विभाग को वास्तविक स्थिति कोर्ट के सामने रखनी चाहिए, न कि उसे गुमराह करने का प्रयास करना चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों की निरीक्षण रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया, जिसमें अस्पताल में पानी रिसाव, बारिश के दौरान कई हिस्सों में जलभराव और लंबे समय से बंद पड़े फायर फाइटिंग सिस्टम जैसी गंभीर खामियां उजागर हुईं। शासन ने अदालत को बताया कि 15 जून 2026 को फायर फाइटिंग सिस्टम की मरम्मत के आदेश जारी कर दिए गए हैं और कार्य तेजी से जारी है।

सीएम हेल्पलाइन से समस्या का हुआ समाधान महिला श्रमिक को मिला संशोधित श्रम कार्ड

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 बनी आमजन का भरोसेमंद सहारा

बिलासपुर। कभी-कभी दस्तावेजों में छोटी सी त्रुटि भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। जिले के बिल्हा विकासखंड के विष्णु नगर, वार्ड क्रमांक-16 निवासी श्रीमती ज्योति यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पति के निधन के बाद उनके श्रम पंजीयन कार्ड में आवश्यक संशोधन नहीं हो पाया, जिसके कारण वे श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रही थीं। श्रीमती यादव ने चॉइस सेंटर के माध्यम से कई बार संशोधन के लिए आवेदन किया, लेकिन लंबे समय तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिरकार उन्होंने 12 जून को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में अपनी शिकायत दर्ज कराई। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी आवाज शासन तक पहुंचेगी और उनकी समस्या का समाधान होगा। शिकायत प्राप्त होते ही श्रम

विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया। संबंधित अधिकारियों ने उन्हें कार्यालय बुलाकर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया। जांच के बाद श्रम पंजीयन कार्ड में आवश्यक संशोधन करते हुए पारिवारिक विवरण अद्यतन किया गया तथा परिवार के सदस्यों की सूची में उनकी पुत्री का नाम भी जोड़ा गया। इसके बाद संशोधित श्रम पंजीयन कार्ड उन्हें उपलब्ध करा दिया गया। संशोधित कार्ड मिलने के बाद अब श्रीमती ज्योति यादव श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की पात्र हो गई हैं। उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होने से उन्हें बड़ी राहत मिली। श्रीमती ज्योति यादव ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई ने शासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज कराने का माध्यम नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्या हल करने का सशक्त मंच है। प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई से आमजन का भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

बालको ने प्राइड मंथ के माध्यम से समावेशी कार्य संस्कृति को किया और मजबूत

कोरबा। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने एक माह तक प्राइड मंथ अभियान चलाया। इस अभियान के माध्यम से कंपनी ने विविध, समानतापूर्ण एवं समावेशी कार्यस्थल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सशक्त किया। इस अभियान में 2,000 से अधिक कर्मचारियों, व्यावसायिक साझेदार एवं समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। अभियान के अंतर्गत जागरूकता सत्र, कर्मचारी सहभागिता कार्यक्रम, प्रतियोगिताएँ, वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएँ, कर्मचारियों की प्रेरक कहानियाँ, क्विज तथा प्राइड मार्च का आयोजन किया गया। इनके माध्यम से एलजीबीटीक्यूआई प्लस समुदाय के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ सहयोग, सम्मान और अपनत्व की संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया। बालको ने ट्रांसजेंडर कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई नीतियाँ लागू की हैं। एजुकेशन सपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत 18 माह की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए 1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही जेंडर रिफर्मेशन पॉलिसी के तहत जेंडर रिफर्मेशन सर्जरी के लिए 2 लाख तक की वित्तीय सहायता तथा 30 दिनों का सवेतन अवकाश उपलब्ध कराया जाता है। अब तक 7 कर्मचारी, इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ये पहल समान अवसर सुनिश्चित करने और मौजूदा अंतरालों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री राजेश सिंह ने कहा, फ्रबालको में हम विविधता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं और समावेशन को एक उच्च प्रदर्शन वाले संगठन की आधारशिला समझते हैं। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ योगदान देने, सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। हमारी प्रतिबद्धता केवल प्रगतिशील नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यस्थल का निर्माण करना है जहाँ सम्मान, समान अवसर और अपनत्व प्रत्येक कर्मचारी के दैनिक अनुभव का हिस्सा हों। वर्तमान में हमारे कार्यबल में 21 ट्रांसजेंडर कर्मचारी कार्यरत हैं और आने वाले वर्षों में हम उनकी भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अतिवृष्टि व बाढ़ नियंत्रण से जुड़े कार्यो तथा जलभराव को दूर करने संबंधित कार्य युद्धस्तर पर संपादित करायें

कोरबा। आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने नगर निगम कोरबा के समस्त जोन कमिश्नरों व मैदान अधिकारी कर्मचारियों को कड़े दिशा निर्देश देते हुये कहा है कि चूंकि मानसून का आगमन हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है, अतः अतिवृष्टि व बाढ़ की स्थिति से निपटने एवं जलभराव को दूर करते हुये जलभराव वाले वार्ड व बस्तियों के नागरिकों को त्वरित राहत एवं बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर करें, इस हेतु सभी आवश्यक तैयारियों को अपडेट रखें, सभी अधिकारी कर्मचारी रात्रि को भी अपना मोबाईल चालू रखें, जोन कमिश्नर अपनी टीमों के साथ क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर स्थिति पर सतर्क नजर रखें। मानसून का आगमन हो चुका है, कोरबा में रविवार से लगातार बारिश हो रही है, निगम के विभिन्न क्षेत्रों व निचली बस्तियों में जलभराव जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है, जिसके समाधान हेतु निगम अमले द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। यहाँ उल्लेखनीय है कि आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान अतिवृष्टि बाढ़ नियंत्रण व प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत तथा आकस्मिक घटना की जानकारी उपलब्ध कराने, इन पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु पूर्व में ही जोनवार टीमों का गठन कर बाढ़ आपदा जैसी स्थिति से निपटने हेतु युद्ध स्तर पर कार्य किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। आज आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में निगम के जोन कमिश्नरों व अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यक बैठक बुलाकर अतिवृष्टि बाढ़ नियंत्रण बचाव व राहत कार्य से जुड़े

निगम द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यो व तैयारियों के संबंध में समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष फोकस रखें- आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों से कहा कि निगम क्षेत्र की निचली बस्तियों तथा अन्य संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष फोकस रखें, इन स्थलों का सतत भ्रमण करें तथा जहाँ कहीं भी जलभराव की स्थिति निर्मित होती है, तत्काल मोटर पम्पों या अन्य उपलब्ध माध्यमों से जल की निकासी करायें, जलभराव से यदि नागरिक प्रभावित होते हैं तथा उनके घरों तक पानी पहुंचता है तो उन्हें तत्काल रेस्क्यू करते हुये सेल्टर केन्द्रों व पहुंचाने की व्यवस्था करें। कंट्रोल रूम स्थापित- इस संबंध में नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र का मुख्य नियंत्रण कक्ष निगम कार्यालय साकेत भवन बनाया गया है, जिसका टेलीफोन नंम्बर 07759-226672 है, मुख्य नियंत्रण कक्ष में स्थापित टेलीफोन अटैंड करने हेतु तीन पालियों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने निर्देशित करते हुए कहा है कि नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं उप प्रभारी जोन कार्यालय में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यकतानुसार मजदूर, हवा भरे ट्यूब, रस्सा, टार्च इत्यादि साधन चैबीसों घंटे तैयार रखेंगे, साथ ही कोरबा शहर में उपलब्ध गोताखोर की जानकारी एवं उनके पते इत्यादि रखकर संपर्क में रहेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोर तत्काल उपलब्ध हो सके।

पूजा शुरू करने से पहले आचमन करना क्यों जरूरी?

जानिए इसकी सही विधि और महत्व

पूजा या किसी भी धार्मिक कार्य को शुरू करने से पहले आचमन किया जाता है। यह एक बहुत जरूरी विधि है, जिसमें मंत्र पढ़ते हुए जल पीया जाता है। कहा जाता है कि आचमन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि करता है। इससे मन एकाग्र होता है और पूजा का फल पूरा मिलता है। सनातन परंपरा में आचमन को पूजा का पहला और अनिवार्य हिस्सा माना गया है।

आचमन क्या है?

आचमन शब्द का अर्थ है जल पीना। पूजा शुरू करने से पहले हम तीन बार मंत्र बोलकर जल पीते हैं। यह सिर्फ जल पीने की क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र तरीका है। जब हम आचमन करते हैं, तो हमारे अंदर की नकारात्मकता दूर होती है और पूजा के लिए हम तैयार हो जाते हैं।

आचमन का धार्मिक महत्व

धार्मिक ग्रंथों में आचमन को बहुत महत्व दिया गया है। इससे तीनों वेद - ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद प्रसन्न होते हैं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक, आचमन करने से कंठ की शुद्धि होती है, जिससे मंत्रोच्चारण साफ और प्रभावी होता है। यह कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों को दूर करता है। आचमन के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है।

आचमन की सही विधि

आचमन हमेशा ब्रह्मतीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्मतीर्थ अंगूठे के मूल भाग में होता है। दाहिने हाथ की अंगुलियों को मिलाकर मुट्ठी बनाएं। फिर उसमें जल लेकर तीन बार मंत्र बोलते हुए पीएं। आचमन के बाद अंगूठे से होंठ पोंछें और हाथ धो लें। अगर जल कम हो तो दाएं कान को छूकर भी आचमन का फल मिल जाता है।

आचमन के मंत्र

आचमन करते समय ये मंत्र बोले जाते हैं:

ॐ केशवाय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ माधवाय नमः

इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल पीने से मन शांत होता है और पूजा में मन लगता है।

तीन बार आचमन क्यों किया जाता है?

तीन बार आचमन करने का विशेष कारण है। पहला आचमन ऋग्वेद को प्रसन्न करता है, दूसरा यजुर्वेद को और तीसरा सामवेद को। तीनों वेदों की तृप्ति से पूजा का पूरा फल मिलता है। तीन की संख्या हिंदू धर्म में बहुत पवित्र मानी जाती है। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा भी प्राप्त होती है।

आचमन से मिलने वाले लाभ:

आचमन करने से मन एकाग्र होता है, शरीर शुद्ध होता है और पूजा का फल दोगुना हो जाता है। यह ना सिर्फ पूजा के लिए, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी शांति और सकारात्मकता लाता है। नियमित आचमन करने से व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है और छोटी-छोटी गलतियां कम होती हैं।

बालों में मेहंदी लगाते समय मिलाएं ये चीजें

बालों की खूबसूरती बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल सदियों से किया जाता रहा है। मेहंदी न सिर्फ बालों को नेचुरल रंग देती है, बल्कि उन्हें मजबूत, घना और चमकदार बनाने में भी मदद करती है। हालांकि, अगर मेहंदी में कुछ खास चीजें मिलाकर लगाई जाएं, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में, जिन्हें मेहंदी में मिलाकर आप अपने बालों को और भी ज्यादा सिल्की और शाइनी बना सकती हैं।

दही :- दही बालों को गहराई से पोषण देने का काम करती है। इसमें मौजूद प्रोटीन और लैक्टिक एसिड बालों का रूखापन कम करते हैं और उन्हें मुलायम बनाते हैं। मेहंदी में दही मिलाने से बाल स्मूद और सिल्की नजर आते हैं।

अंडा:- इंडे और डैमेज बालों के लिए अंडा बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देता है और उनकी चमक बढ़ाता है। यह प्राकृतिक कंडीशनर की तरह काम करता है।

चाय का पानी:- मेहंदी को भिगोने के लिए साधारण पानी की जगह चाय का पानी इस्तेमाल करें। इससे बालों में रंग ज्यादा गहरा आता है और बाल अधिक चमकदार दिखाई देते हैं।

कॉफी पाउडर:-अगर आप बालों में गहरा रंग चाहती हैं, तो मेहंदी में कॉफी पाउडर मिलाएं। इससे बालों को नेचुरल ब्राउन टोन मिलता है और उनकी चमक भी बढ़ती है।

एलोवेरा जेल:- एलोवेरा बालों में नमी बनाए रखने में मदद करता है। मेहंदी में एलोवेरा जेल मिलाने से बाल मुलायम, चमकदार और हाइड्रेटेड बने रहते हैं।

आंवला पाउडर:-आंवला विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह बालों को मजबूत बनाने के साथ-साथ समय से पहले सफेद होने की समस्या को कम करने में भी मदद कर सकता है।

नारियल या सरसों का तेल:-मेहंदी बालों को थोड़ा ड्राई कर सकती है। ऐसे में इसमें थोड़ा नारियल या सरसों का तेल मिलाने से बालों की नमी बनी रहती है और वे अधिक चमकदार दिखते हैं।

मेहंदी लगाने का सही तरीका:- मेहंदी को रातभर भिगोकर रखें। सुबह इसमें अपनी जरूरत के अनुसार ऊपर बताए गए इंग्रीडिएंट्स मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें। इसे बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक अच्छी तरह लगाएं और 2 से 3 घंटे बाद साफ पानी से धो लें।

सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं ये चीजें

महादेव का मिलेगा आशीर्वाद

सावन भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र महीना है। इस बार सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान शिव भक्त कावड़ यात्रा, जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन सावन शुरू होने से पहले कुछ खास चीजें घर लाकर रख लेने से पूरे महीने शिव कृपा बनी रहती है। इन वस्तुओं को घर में लाने से ना सिर्फ वातावरण शुद्ध होता है बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि और शांति भी बढ़ती है।

रुद्राक्ष: शिव का प्रतीक

सावन शुरू होने से पहले रुद्राक्ष लाकर घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है। इसे पूजा घर में रखने या धारण करने से रुके हुए काम बनते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। रुद्राक्ष की ऊर्जा घर में सकारात्मकता का संचार करती है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करती है।

भस्म: शिव का श्रृंगार

भस्म भगवान शिव का प्रिय श्रृंगार है। सावन से पहले थोड़ी सी शुद्ध भस्म घर लाकर पूजाघर में रख लें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण पवित्र रहता है। भस्म रखने से शिव जी की कृपा बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति मिलती है।

डमरू: शिव की ध्वनि

डमरू भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। सावन शुरू होने से पहले छोटा सा डमरू घर लाकर पूजा घर में रखें। डमरू की ध्वनि घर के वातावरण को शुद्ध करती है और तनाव को कम करती है। मान्यता है कि जहां डमरू होता है, वहां अमंगल नहीं आता है।

चांदी का कड़ा: शिव का आभूषण

धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं। सावन से पहले चांदी का कड़ा घर लाकर रखें। इसे स्वयं पहनने से भी शिव कृपा प्राप्त होती है। चांदी का कड़ा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और परिवार की रक्षा करता है।

त्रिशूल: शिव का अस्त्र

त्रिशूल तीन देवों और तीन लोकों का प्रतीक है। सावन शुरू होने से पहले चांदी या तांबे का छोटा त्रिशूल घर लाकर पूजा घर में स्थापित करें। इससे अपदाओं का भय दूर होता है और बुरी शक्तियों का नाश होता है। त्रिशूल घर में सकारात्मकता और सुरक्षा का वातावरण बनाता है।

गंगाजल

गंगाजल शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन शुरू होने से पहले शुद्ध गंगाजल की बोतल घर लाकर रखें। पूरे सावन महीने इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। गंगाजल घर की नकारात्मकता को दूर करता है और शिव कृपा को आमंत्रित करता है।

जल का नया पात्र

सावन में जलाभिषेक के लिए नया पात्र जैसे लोटा या कलश लाना शुभ होता है। इसे सावन शुरू होने से पहले घर ले आएं। नया पात्र शिव पूजा को और अधिक फलदायी बनाता है। इससे पूजा की पवित्रता बढ़ती है और भोलेनाथ की कृपा घर में बनी रहती है। सावन शुरू होने से पहले इन सात चीजों को घर लाकर रख लेने से पूरे महीने शिव आराधना फलदायी होती है। ये वस्तुएं ना सिर्फ पूजा को पूर्ण करती हैं बल्कि घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाती हैं। सच्चे मन से इनका उपयोग करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है।

आज का राशिफल

मेष राशि - कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यक्षमता को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। स्वास्थ्य में माता का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। कल आप किसी बड़े निर्णय को लेने में सक्षम होंगे।

वृषभ राशि - लव लाइफ में साथी के साथ संबंध और अधिक मधुर होंगे और आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहेगा और आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। कल का दिन नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी पुराने मित्र से मिल सकते हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन राशि - बिजनेस में किसी को भी बिना जांच-परख के उधार न दें। लव लाइफ में वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके गलत शब्द रिश्ते में खटास पैदा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से गले या आंखों का थोड़ा ध्यान रखें। धन संबंधी मामलों में बहुत सतर्क रहें और सोच-समझकर ही पैसा खर्च करें।

कर्क राशि - बिजनेस में लाभ के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आपको नई उपलब्धियां मिलेंगी और आपके नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी। लव लाइफ में साथी के साथ रोमांटिक पल व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप मन से भी काफी प्रसन्न रहेंगे। कल आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा।

सिंह राशि - काम का दबाव हो सकता है और किसी अनचाहे खर्च का सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस में सावधानी बरतें और किसी पर भी बिना सोचे-समझे भरोसा न करें। लव लाइफ में साथी के साथ थोड़ा दूरी महसूस हो सकती है, इसलिए बातचीत जारी रखें। आध्यात्मिक कार्यों या योग-ध्यान में रुचि लेने से मन को शांति प्राप्त होगी।

कन्या राशि - आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बिजनेस में अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं। लव लाइफ में साथी के साथ बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे और आप भविष्य की सुखद योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप अपने मित्रों के साथ एक खुशनुमा दिन बिताएंगे।

तुला राशि-बिजनेस में नई योजनाएं सफल होंगी और व्यापारिक सौदों में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी लव लाइफ में साथी के साथ तालमेल बहुत ही सुंदर रहेगा और आपसी प्रेम गहरा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है, ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा।

वृश्चिक राशि -स्वास्थ्य के प्रति आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे, ऊर्जा का संचार बना रहेगा। कल आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में रुचि ले सकते हैं। आपका मन शांत रहेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। मेहनत का सकारात्मक फल मिलेगा।

धनु राशि-फालतू की बातों में समय न गंवाएं। बिजनेस में अभी किसी भी प्रकार के बड़े निवेश को टालना ही बेहतर होगा। लव लाइफ में साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, उनका ध्यान रखें। स्वास्थ्य में पेट या पाचन से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और हल्का भोजन लें।

मकर राशि - योजनाबद्ध तरीके से काम करें। साझेदारी वाले कार्यों से लाभ मिलने की संभावना है। बिजनेस में अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें लव लाइफ में साथी के साथ रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य है, बस नियमित खान-पान का ध्यान रखें।

कुंभ राशि- आपके विरोधी शांत रहेंगे। बिजनेस में लाभ की अच्छी स्थिति बनी रहेगी। लव लाइफ में साथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे और आप दोनों एक-दूसरे की बातों को बेहतर समझेंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा और आप नई स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। रोगों और शत्रुओं पर विजय दिलाने में मददगार साबित होगा।

मीन राशि- आप अपने काम में निखार ला पाएंगे। आपके रचनात्मक विचारों की प्रशंसा होगी बिजनेस में कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, बशर्ते आप सही योजना बनाएं। लव लाइफ में साथी के साथ हल्की-फुल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन प्रेम बना रहेगा।

चुकंदर-सेब की हेल्दी और टेस्टी जेली रेसिपी

अगर आप भी बिना केमिकल और प्रिजर्वेटिव के कुछ मीठा बनाना चाहते हैं, तो यह चुकंदर, सेब और गाजर से बनी जेली एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेसिपी न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खास बात ये है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और समय भी कम लगता है। चलिए जानते हैं इसे बनाने का तरीका...

सामग्री:

चुकंदर – 150 ग्राम, सेब – 200 ग्राम,गाजर – 250 ग्राम,संतरा – 100 ग्राम, अनार – 60 ग्राम
पानी – 350 मिलीलीटर, नींबू का रस – 1 टेबलस्पून, शहद – 1 टीस्पून, अगर-अगर पाउडर – 1 टीस्पून।

बनाने की विधि

सबसे पहले 150 ग्राम चुकंदर, 200 ग्राम सेब और 250 ग्राम गाजर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन्हें ब्लेंडर में डालें और साथ में 100 ग्राम संतरा, 60 ग्राम अनार और 350 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छी तरह स्मूद होने तक ब्लेंड करें। तैयार मिश्रण को छानकर एक बाउल में निकाल लें। इसमें 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून शहद और 1 टीस्पून अगर-अगर पाउडर डालें और अच्छे से फेंट लें। अब इस मिश्रण को एक पैन में डालकर 3–4 मिनट तक उबालें। गैस बंद करें और मिश्रण को 5 मिनट तक ठंडा होने दें। अब इसे किसी ट्रे या डिश में डालें और 15 मिनट के लिए सेट होने दें, फिर 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। सेट होने के बाद इसे अपनी पसंद के आकार में काट लें। स्वादिष्ट और हेल्दी ABC गमीज तैयार हैं, सर्व करें।

फायदे

ये जेली जितनी टेस्टी बनकर तैयार होती है, उतनी ही हेल्दी भी होती है। इसके कई फायदे है, जैसे- चुकंदर और गाजर खून बढ़ाने में मदद करते हैं, सेब और अनार इम्यूनिटी मजबूत करते हैं। यह रेसिपी बिना जिलेटिन के पूरी तरह शाकाहारी है और बच्चों के लिए भी हेल्दी और टेस्टी स्नैक है।

बारिश के मौसम में वैक्सिंग करना हो जाता है मुश्किल?

बारिश का मौसम जितना सुहाना लगता है, उतनी ही मुश्किलें यह हमारी त्वचा की देखभाल के लिए भी लेकर आता है। इस मौसम में उमस और पसीना इतना ज्यादा होता है कि छोटी-छोटी चीजें भी परेशानी बन जाती हैं। इन्हीं में से एक है वैक्सिंग। कई बार वैक्स त्वचा पर ठीक से लगती ही नहीं या फिर स्ट्रिप हटाने के बाद भी जगह-जगह चिपकी रह जाती है। इससे ना सिर्फ ज्यादा दर्द होता है, बल्कि वैक्सिंग का नतीजा भी अच्छा नहीं मिलता। अगर आपके साथ भी हर मानसून यही परेशानी होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक छोटा-सा तरीका अपनाकर आप वैक्सिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक बना सकते हैं।

क्या है आसान हैक?

इस हैक के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी और वह है पाउडर। वैक्सिंग शुरू करने से पहले जिस हिस्से पर वैक्स करनी है, वहां हल्का-सा पाउडर लगा लें। पाउडर त्वचा की नमी और पसीने को सोखने में मदद करता है। इसके बाद वैक्स लगाएं और सामान्य तरीके से स्ट्रिप का इस्तेमाल करें। अगर चाहें, तो स्ट्रिप पर भी थोड़ा-सा पाउडर छिड़क सकते हैं।

इससे क्या फायदा हो सकता है?

वैक्स बेहतर तरीके से चिपकती है: जब त्वचा सूखी रहती है, तो वैक्स बालों को बेहतर तरीके से पकड़ पाती है।

कम दर्द महसूस होता है: एक ही जगह पर बार-बार वैक्स लगाने की जरूरत कम पड़ती है, जिससे दर्द भी कम हो सकता है।

त्वचा पर कम चिपकती है वैक्स: नमी कम होने की वजह से वैक्स त्वचा पर फैलने या चिपकने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।

बारिश में वैक्सिंग करते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

वैक्सिंग से पहले त्वचा अच्छी तरह साफ कर लें। अगर शरीर पर पसीना है, तो पहले उसे सूखे तौलिए से पोंछ लें। बहुत ज्यादा गर्म कमरे में वैक्सिंग करने से बचें। वैक्सिंग के बाद कुछ घंटों तक बहुत टाइट कपड़े ना पहनें। त्वचा को ठंडक देने वाला हल्का जेल या लोशन लगा सकते हैं।

बुखार, डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह

मानसून की शुरुआत के साथ ही मुंबई में डेंगू, मलेरिया, बुखार और अन्य संक्रमक बीमारियों के मामलों में सामान्यत: वृद्धि देखने को मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत की अग्रणी स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से एक स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनएसई: STARHEALTH; बीएसई: 543412) ने मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में अपने मानसून स्वास्थ्य जागरूकता और सहायता अभियान को और मजबूत किया है।

स्टार हेल्थ के वित्त वर्ष 2025-26 के मुंबई एमएमआर आंकड़ों के अनुसार, बुखार और संक्रमक बीमारियों के लिए होम हेल्थकेयर सेवाओं के उपयोग में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही, कंपनी की हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन ओपीडी सेवा को भी देशभर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और बढ़ती संख्या में ग्राहक इसे चिकित्सा परामर्श के पहले विकल्प के रूप में अपना रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर चिकित्सा हस्तक्षेप को बढ़ावा देना है। इसके तहत पॉलिसीधारकों को टॉक टु स्टार और होम हेल्थकेयर सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, जबकि आम जनता को स्टार हेल्थ कस्टमर एप के माध्यम से नि:शुल्क 24x7 (सातों दिन 24 घंटे) ऑनलाइन ओपीडी परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस हेड (मुंबई एमएमआर और गोवा) श्री धीरज गोयल ने कहा, "मुंबई में मानसून के दौरान बुखार, डेंगू, मलेरिया और संक्रमण के मामलों में वृद्धि होना एक सामान्य बात है, लेकिन अक्सर परिवार लक्षण गंभीर होने तक इंतजार करते रहते हैं। इस मौसम में हमारा प्रयास चिकित्सा सहायता तक पहली पहुंच को आसान बनाना है। पॉलिसीधारक होम हेल्थकेयर या नियोजित अस्पताल भर्ती सहायता के लिए टॉक टु स्टार पर 7676 905 905 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जबकि आम लोग स्टार हेल्थ एप के माध्यम से नि:शुल्क 24x7 वर्चुअल ओपीडी परामर्श बुक कर सकते हैं। समय पर चिकित्सकीय सलाह इस मौसम में महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकती है।" राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 2026 में जारी घरेलू स्वास्थ्य व्यय पर 80वें दौर के सर्वेक्षण के आंकड़े बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को रेखांकित करते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल में भर्ती होने की औसत लागत 44,580 रुपये, जबकि शहरी महाराष्ट्र में 67,831 रुपये है। अस्पताल में भर्ती होने का लगभग 90 प्रतिशत खर्च परिवारों और व्यक्तियों को अपनी जेब से वहन करना पड़ता है।

एस आर हॉस्पिटल चिखली में आधी रात को डॉक्टरों द्वारा जटिल ऑपरेशन कर युवक को दिया जीवनदान

डॉ. नीरज भुसखरे,सर्जन

दुर्ग। चिखली स्थित एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक की जान बचा ली। पेट के असहनीय दर्द से तड़प रहे एक युवक की आंतें हर्निया में फंस गई थीं, जिसका डॉक्टरों की टीम ने रात में ही सफल ऑपरेशन किया। समय पर इलाज मिलने से युवक के शरीर में जहर फैलने का खतरा टल गया और अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है।

आंतों में रुक गया था खून का बहाव- अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, युवक को अचानक पेट में तेज दर्द उठा, जिसके बाद उसे बेहद गंभीर हालत में देर रात आपातकालीन (इमरजेंसी) वार्ड में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि युवक की आंतें हर्निया में बुरी तरह फंस चुकी हैं, जिससे वहां खून का प्रवाह (ब्लड सर्कुलेशन) पूरी तरह बंद हो गया था। रक्तसंचार रुकने के कारण पेट के उस हिस्से में गैंग्रीन (मांस का सड़ना) बन चुका था, जो जानलेवा साबित हो सकता था।

चेयरमैन की तत्परता से आधी रात को जुटी टीम - मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज के चेयरमैन संजय तिवारी ने आधी रात को ही मोर्चा संभाला। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की पूरी टीम को एक्टिव किया और सभी को तत्काल अस्पताल पहुंचने के निर्देश दिए। डॉक्टरों ने बताया कि अगर चेयरमैन समय पर पूरी मेडिकल टीम को तैनात नहीं करते, तो मरीज के पूरे शरीर में गैंग्रीन का जहर फैल सकता था।गैंग्रीन को काटकर अलग किया, मरीज अब सुरक्षितइसके बाद डॉक्टरों की विशेष टीम, जिसमें सर्जन डॉ. नीरज भुसखरे, डॉ. अश्विनी शुक्ला, डॉ. अपूर्वा अग्रवाल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. रंजन सेन गुप्ता शामिल थे, उन्होंने फौरन ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर पेट के प्रभावित हिस्से से गैंग्रीन को काटकर सुरक्षित अलग कर दिया। सफल ऑपरेशन के बाद युवक को तेज दर्द से राहत मिल गई है और वह तेजी से रिकवर हो रहा है।

महापौर ने सभी नवनियुक्त एल्डरमेन से कहा सुझावों पर मिलजुलकर करेंगे अमल

नगर निगम सभागृह में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया

राजनांदगांव। शहर के 8 नामांकित पार्षदों का नगर निगम में स्वागत किया गया। महापौर मधुसूदन यदवन ने कहा कि पार्षदों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों का हमारा निगम परिवार है, जिसमें हम सब मिल जुलकर शहर विकास के लिए काम करते है। अब हमारे नामांकित पार्षद भी हमारे इस परिवार से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय एक ऐसी संस्था है, जहां सुबह से रात तक काम रहता है और उनका मूल काम जनता को मुलभूत सुविधा उपलब्ध कराना एवं उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उन्होनें कहा कि सभी नामांकित पार्षदों को सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। शहर विकास में आप सब का सुझाव एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिसके लिए हम सब मिल जुलकर काम करेंगे। नामांकित पार्षद नागेश यदु, करूणा राजपूत, हर्ष रामटेके, सूर्यकांत वास, मंजू यादव, भीषम देवांगन, कृति बोरकर, देवाशिष झा का महापौर सहित आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। आयुक्त विश्वकर्मा ने भी मनोनित पार्षदों का स्वागत करते हुए कहा कि अब हमारे परिवार में महापौर सहित 60 निगम पदाधिकारी हो गए, जिससे विकास कार्य में गति आयेगी मैं आप सभी से शहर विकास में सहयोग की अपेक्षा करता हूं। कार्यक्रम के अंत में पद्म विभुषण से सम्मानित पंडवानी गायिका स्व. मती तिजन बाई द्वारा महाभारत को पंडवानी के माध्यम से दी गयी प्रस्तुति को यादकर छत्तीसगढ़ की पहचान देश-विदेश में दिलाने पर उन्हे नमन करते हुए मौन श्रद्धांजलि दी गई।

वीएलई को श्रमिक डेटा अपडेट और ई-केवाईसी का दिया गया प्रशिक्षण

दुर्ग। जिले के श्रमिकों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राधाकृष्ण सभागार, साइंस कॉलेज दुर्ग में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के वीएलई संचालकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सहायक श्रमायुक्त से प्राप्त जानकारी अनुसार कार्यशाला में वीएलई संचालकों को आधार के अनुरूप श्रमिकों के डेटा संशोधन तथा ई-केवाईसी प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वीएलई द्वारा कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। प्रभारी सहायक श्रमायुक्त पायल शर्मा, श्रम निरीक्षक बसंत वर्मा एवं श्रम कल्याण अधिकारी डॉ. टुकेन्द्र कुमार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी एवं व्यवहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके समाधान की जानकारी दी। कार्यशाला में राज्य स्तरीय मैनेजर नीता साहू एवं जिला मैनेजर प्रकाश अंसारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के डेटा सुधार के लिए शासन द्वारा 20 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

प्रशिक्षण के दौरान वीएलई संचालकों से अपील की गई कि वे श्रमिकों का डेटा समय पर अपडेट कर ई-केवाईसी पूर्ण कराएं, ताकि पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

सुपोषण के लिए जनआंदोलन बनेगा 'सुपोषण वृक्ष-मुनगा' अभियान, महापौर ने लगाया मुनगा पौधा

222 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगाए जाएंगे मुनगा के पौधे, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण पहल,

दुर्ग। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुपोषण वृक्ष-मुनगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नगर निगम क्षेत्र के सभी 222 आंगनबाड़ी केंद्रों में मुनगा के पौधों का रोपण किया जाएगा। इसका उद्देश्य मुनगा के पौष्टिक गुणों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इसे जनआंदोलन का स्वरूप देना है। इसी कड़ी में आज पोलसाय पारा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महापौर अलका बाघमार ने मुनगा का पौधा रोपकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य देव नारायण चन्द्राकर, शेखर चन्द्राकर, नीलेश अग्रवाल, शशि साहू, पार्षद रंजीता पाटिल, सावित्री दमाहे, सुरूचि उमरे, सरिता चन्द्राकर, गौरव शर्मा, तेखन सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी अनिता सिंह तथा विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि मुनगा को 'सुपोषण का वृक्ष' कहा जाता है। इसकी पत्तियों, फलियों एवं अन्य भागों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन तथा अन्य आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके नियमित उपयोग से बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुपोषण के खिलाफ यह अभियान केवल शासकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला सामाजिक अभियान है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वर्षा ऋतु पौधरोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। प्रत्येक परिवार अपने घर, आंगन, खेत, विद्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर मुनगा के पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प ले। 'घर-घर मुनगा, हर घर मुनगा' का संदेश जन-जन तक पहुंचाकर इस अभियान को जनआंदोलन बनाया जाए, ताकि स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य साकार हो सके।आज आंगनबाड़ी केंद्रों में तिथि न्योता भोज का आयोजन किया गया महापौर एवम उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने बच्चों को खीर पुरी परोसा एवम सुपोषण किट वितरित किया।

ई-बीट सिस्टम की शुरूआत, पेपरलेस वर्क, रियल टाइम लोकेशन मिलेगा, और ऑनलाइन होगी मॉनिटरिंग

मोहला-मानपुर जिले में राजनांदगांव रेंज आईजी बालाजी राव ने किया नए सिस्टम को लॉच

रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक रहे उपस्थितत, नई तकनीक का मिलेगा फायदा

राजनांदगांव। नई पहल करते हुए राजनांदगांव रेंज अब ई-बीट सिस्टम लागू किया जाएगा। इसकी शुरूआत मंगलवार को मोहला-मानपुर-चौकी जिले से हुई है। इस दौरान रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। नए सिस्टम का सबसे फायदा ये होगा कि यह पेपरलेस होगा, बीट अधिकारी की रियल टाइम लोकेशन रहेगी और ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। ई-बीट सिस्टम को आईजी बालाजी राव ने शुरू किया और कहा कि इसका बेहतर विभागीय टीम और आमजनों को मिलेगा। यह एक अत्याधुनिक डिजिटल पुलिसिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से बीट अधिकारी अपने क्षेत्र में किए गए भ्रमण, गश्त, सत्यापन, संदिग्ध व्यक्तियों, आदतन अपराधियों, जनसंपर्क गतिविधियों एवं अन्य पुलिस कार्यों का विवरण ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इससे वरिष्ठ अधिकारी वास्तविक समय में बीट गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे तथा निर्देश जारी कर सकेंगे। अब तक बीट पुलिसिंग मैनुअल रजिस्टर एवं बीट डायरी के माध्यम से संचालित होती थी, जिससे सूचनाओं के संकलन, विश्लेषण एवं मॉनिटरिंग में समय लगता था। ई-बीट सिस्टम लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी एवं अधिक प्रभावी हो जाएगी।

ई-बीट सिस्टम की प्रमुख विशेषताएं

बीट अधिकारियों की रियल-टाइम लोकेशन एवं गश्त की ऑनलाइन मॉनिटरिंग। संदिग्ध व्यक्तियों, आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों का डिजिटल डाटाबेस तैयार कर प्रभावी निगरानी। बीट क्षेत्र में नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं सुरक्षा समितियों से प्राप्त जानकारी एवं शिकायतों का ऑनलाइन संधारण एवं त्वरित निराकरण। अपराध के पैटर्न का डेटा आधारित विश्लेषण कर संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी पुलिसिंग। पेपरलेस, पारदर्शी एवं जवाबदेह पुलिसिंग को बढ़ावा।

तकनीकी विशेषताएं

ई-बीट सिस्टम को सुरक्षित, उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली के अनुरूप विकसित किया गया है। थाना प्रभारी, एसडीओपी एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान, निगरानी एवं सुपरविजन अधिक प्रभावी हो सके। सीमित नेटवर्क वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए भी इस प्रणाली को व्यवहारिक एवं उपयोगी बनाया गया है। पुलिस महानिरीक्षक ने इसे स्मार्ट एवं तकनीक आधारित पुलिसिंग की दिशा में एक अनुकरणीय पहल बताते हुए राजनांदगांव रेंज के सभी जिलों में इस प्रणाली को चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए।

भाजपा चरोदा मंडल ने मनाई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, राष्ट्र निर्माण में योगदान को किया याद

भिलाई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान शिक्षाविद् डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा चरोदा मंडल द्वारा श्रद्धा एवं सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के आह्वान तथा प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष ए. गौरीशंकर ने किया। कार्यक्रम का आयोजन चरोदा स्थित साईं मंदिर परिसर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने देश की अखंडता और एकात्मता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा उनका जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम में चरोदा मंडल प्रभारी विजेंद्र सिंह, अहिवारा विधानसभा विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, मंडल अध्यक्ष ए. गौरीशंकर, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ खिलावन साहू, उपनेता प्रतिपक्ष चंद्र प्रकाश पांडे सहित अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा महामंत्री पूर्णिमा ठाकुर, राजेश कुमार मौर्य, मंडल उपाध्यक्ष परमजीत सिंह, प्रमिला टांडी, वेद प्रकाश पांडे, तरुण परगनिया, टी. रमन, हेमराज साहू, रोहित चौधरी, मनोज चक्रधारी, राजेश यादव, नितेश कुशवाहा, मनजीत लहरे, अनु वर्मा, अभय चौबे, आशीष बोरकर, ममता सिंह, पूनम श्रीवास्तव, रेखा साहू, कल्पना बाला, रितु वर्मा, उषा चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कायक्रम के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। अंत में राष्ट्रहित एवं संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने का आह्वान किया गया।

महादेव बेटिंग ऐप का मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ओमान में गिरफ्तार, भारत लाने की प्रक्रिया शुरू

लोकतंत्र प्रहरी / विशेष संवाददाता/ नई दिल्ली, 8 जुलाई। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के मुख्य प्रमोटर और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को ओमान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंद्राकर पर फर्जी इंडोनेशियाई पासपोर्ट के जरिए ओमान में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप है। इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत सरकार ने उसे वापस देश लाने के लिए औपचारिक प्रत्यर्पण (Extradition) प्रक्रिया तेज कर दी है। फिलहाल उसे ओमान की राजधानी मस्कट स्थित अल खौद हाई सिक्योरिटी डिटेंशन सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है।

रेड नोटिस के आधार पर हुई कार्रवाई- आधिकारिक सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी किए गए रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर रॉयल ओमान पुलिस ने यह कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ के भिलाई का मूल निवासी सौरभ चंद्राकर पिछले कई वर्षों से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में छिपकर रह रहा था और वर्ष 2019 से ही भारतीय कानून और जांच एजेंसियों की पकड़ से बाहर चल रहा था।

5,000 करोड़ से अधिक का घोटाला- सौरभ चंद्राकर को महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क का मुख्य संचालक माना जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस सिंडिकेट के जरिए देश-विदेश में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के काले साम्राज्य को चलाया जा रहा था।

इंटरपोल ने खारिज की थी याचिका- हाल ही में चंद्राकर को उस वक्त बड़ा झटका लगा था जब इंटरपोल की 'कमीशन फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरपोल्स फाइल्स' (CCF) ने उसके खिलाफ जारी रेड नोटिस को हटाने की याचिका खारिज कर दी थी। चंद्राकर ने दावा किया था कि भारत में उसके खिलाफदर्ज मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। हालांकि, सीसीएफ ने उसके दावों को नकारते हुए माना कि यह पूरी तरह वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला है, इसलिए रेड नोटिस जारी रखना बिल्कुल उचित है।

अब तक की बड़ी कार्रवाइयां- वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस पूरे घोटाले की सघन जांच कर रहे हैं। जांच एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

* देश भर में 175 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है।
* इस मामले में अब तक 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 74 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
* रायपुर की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत में 5 चार्जशीट (अभियोजन शिकायतें) दाखिल की जा चुकी हैं।
* जांच एजेंसियों ने अब तक लगभग 4,336 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां जब्त, फ्रीज या अटैच की हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां ओमान सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि कानूनी कागजी कार्रवाई को जल्द पूरा कर सौरभ चंद्राकर को भारत डिपोर्ट या प्रत्यर्पित कराया जा सके।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायलीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com